

सार्वजनिक जन जागरूकता सर्वेक्षण
आयोजित करने हेतु वित्तीय बोली
आमंत्रित करने की सूचना
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल,
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई – 400 008

यह दस्तावेज़ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए डीआईसीजीसी को उत्तर देने के उद्देश्य को छोड़कर, डीआईसीजीसी की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानूनों के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण और प्रकटीकरण:

निकेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), मुंबई ने इच्छुक पार्टियों को 'सर्वेक्षण परियोजना' की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि डीआईसीजीसी ने यहां निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानते हैं, न तो डीआईसीजीसी और न ही इसके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त या निहित करते हैं जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है।

डीआईसीजीसी, मुंबई ने अप्रैल 2025 से मार्च 2028 की अवधि के लिए विभिन्न सर्वेक्षण करने के लिए परिवारों और उद्यमों (आरबीआई/डीएसआईएम-केंद्रीय कार्यालय विभाग/अन्य/6/24-25/ईटी/903 [सर्वेक्षण एजेंसियों का पैनेल]) पर सर्वेक्षण करने के लिए 25 अगस्त, 2025 को सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसियों के पैनेल के उत्तर में चयनित पैनेल वाली सर्वेक्षण एजेंसियों से वित्तीय कोटेशन के लिए बोली आमंत्रित करने के लिए यह नोटिस तैयार किया है। 'जन जागरूकता सर्वेक्षण' करने के लिए पैनेल में शामिल सर्वेक्षण एजेंसियों से वित्तीय कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। सूचीबद्ध सर्वेक्षण एजेंसियों की सूची के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx?Id=23292 देखें। पैनेल में शामिल एजेंसियों से अनुरोध है कि वे अपनी वित्तीय बोली मेसर्स एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से जमा करें।

यह जानकारी संपूर्ण होने का दावा नहीं करती। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की जाँच-पड़ताल करना आवश्यक है, और उन्हें लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा कर लिया है तथा बोली जमा करते समय वे केवल डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह डीआईसीजीसी या उसके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है।

डीआईसीजीसी बोली के साथ आगे न बढ़ने या किसी भी स्तर पर बोली के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह इस दस्तावेज में निर्दिष्ट समय-सीमा को संशोधित करने या आवश्यक समझे जाने पर बोली प्रक्रिया या प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्ष के साथ आगे की चर्चा में शामिल होने से इनकार कर सकता है। इस बोली के संबंध में पार्टियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की लागतों की कोई प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

एनआईटी के उत्तर में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और एनआईटी के उत्तर में प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के लिए बोली लगाने वाली कंपनी को बाध्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता को एक घोषणा देनी चाहिए और प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करना चाहिए कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और बोली लगाने का अधिकार प्राप्त है। एनआईटी दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। कोई भी स्पष्टीकरण dicgcimdac@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

नोट: यह सूचना केवल सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है तथा इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए कोई खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भाग लेने के लिए केवल आमंत्रित पक्षों को अनुमति है तथा यह चयनित खरीददार संगठन के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक ही सीमित है। अनुरोध के बिना प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।

वित्तीय बोली जमा करने की अनुसूची

ई-निविदा संख्या	डीआईसीजीसी/निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम /आईएमडीएसी////[सर्वेक्षण]
बोली का माध्यम	ई-खरीद प्रणाली https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi
एमएसटीसी की वेबसाइट पर वित्तीय बोली दस्तावेज अपलोड करने की तिथि	22 मई 2026
एमएसटीसी की वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तारीख	22 मई 2026
वित्तीय बोली शुरू होने की तिथि	22 मई 2026, 05:00 अपराह्न
वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि	12 जून 2026, 06:00 अपराह्न
सर्वेक्षण की अनुमानित लागत	₹ 17,75,500/-
बयाना जमाराशि	₹ 35,510/- बोलीदाताओं को अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/) में ईएमडी की स्कैन की गई प्रतियां या एनईएफटी के प्रमाण को अपलोड करना होगा। बैंक गारंटी की मूल प्रति या एनईएफटी के प्रमाण की बोली खोलने से पहले संचार के पते पर पहुंच जानी चाहिए।
ईएमडी भेजने के लिए पता (लिफाफे पर आरएफक्यू का नाम इंगित करते हुए)	मुख्य महाप्रबंधक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई – 400 008
लेनदेन शुल्क	शून्य
ई-निविदा खोलने की तिथि, समय और स्थान	15 जून 2026: 03:00 अपराह्न (केवल भौतिक उपस्थिती द्वारा) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई – 400 008
यदि कोई प्रश्न हो तो संपर्क सूत्र:	
डीआईसीजीसी:	
<ol style="list-style-type: none"> श्री भास्कर शिवशंकर बिराजदार, सहायक सलाहकार, मोबाइल: 7021740368, ई-मेल: bsbirajdar@rbi.org.in श्री दीपक कुमार जेना, सहायक प्रबंधक, मोबाइल: 9777337734, ई-मेल: deepakjena@rbi.org.in 	
मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड:	
विक्रेताओं के लिए केंद्रीकृत हेल्पडेस्क: 07969066600	
ईमेल आईडी: helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)	
विक्रेताओं के लिए एमएसटीसी मुंबई में हेल्पडेस्क: 7651915418/022 6985 6817/022 6985 6800 (उपलब्धता: सभी तकनीकी विषयों (ई-निविदा, प्रणाली सेटिंग्स आदि) के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)	

1. जन जागरूकता सर्वेक्षण (पीएस)

- 1.1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के कार्य डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बनाए गए 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' (डीआईसीजीसी अधिनियम) और 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियम, 1961' के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। डीआईसीजीसी अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह जमा बीमा और प्रत्यय सुविधाओं की गारंटी और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के उद्देश्य से एक निगम की स्थापना के लिए प्रदान करने वाला एक अधिनियम है। डीआईसीजीसी की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह से आरबीआई द्वारा जारी और अभिदत्त है। डीआईसीजीसी का प्रबंधन इसके निदेशक मंडल के पास निहित है, जिसमें आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर अध्यक्ष होता है।
- 1.2. डीआईसीजीसी ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में अपने कार्यकरण, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता के स्तर का आकलन करने और समझने के उद्देश्य से जन जागरूकता सर्वेक्षण (पीएस) शुरू करने का प्रस्ताव किया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य जमा बीमा के बारे में जनता की समझ, डीआईसीजीसी की पहलों और योजनाओं के बारे में उनके ज्ञान और डीआईसीजीसी की दृश्यता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के बारे में उनकी समग्र धारणा पर डेटा एकत्र करना है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां जन जागरूकता में सुधार की आवश्यकता है और हितधारकों के बीच समझ और विश्वास बढ़ाने के लिए लक्षित संचार रणनीतियों और शैक्षिक अभियानों को विकसित करने में डीआईसीजीसी की सहायता कर सकता है।
- 1.3. सर्वेक्षण 15 राज्यों (19 शहरों) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (3 शहरों) में आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 6,700 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण में दो चरणों की नमूना पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जिसमें मतदान केंद्रों/गांवों को पहले चरण की इकाइयों (एफएसयू) के रूप में और घरों को दूसरे चरण की इकाइयों (एसएसयू) के रूप में शामिल किया जाएगा। जबकि एफएसयू का चयन सर्कुलर सिस्टमैटिक सैंपलिंग का उपयोग करके किया जाता है, एसएसयू का चयन दस घरों को छोड़कर दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करके किया जाता है। सर्वेक्षण प्रश्नावली अनुलग्नक ए में दी गई है।
- 1.4. एजेंसी के कार्यालय अनुलग्नक बी में दिए गए लक्षित राज्यों में स्थित होने चाहिए। बोलियां खोलने से पहले इसका प्रमाण संचार के पते पर पहुंचना चाहिए। उक्त प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में बोली अमान्य हो जाएगी।

2. कार्य का दायरा

एजेंसी द्वारा डीआईसीजीसी को प्रदान किए जाने वाले आउटसोर्सिंग कार्य का दायरा निम्नानुसार वर्णित है:

- 2.1. **सर्वेक्षण आवृत्ति:** सर्वेक्षण एक बार का कार्य होगा।

- 2.2. सर्वेक्षण कवरेज:** सर्वेक्षण 15 राज्यों (19 शहरों) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुलग्नक बी में किया गया है। डीआईसीजीसी द्वारा सुझाए गए नमूना डिजाइन का पालन किया जाना चाहिए। डीआईसीजीसी, अपने विवेक पर, बिना कोई कारण बताए भौगोलिक कवरेज को बढ़ा या घटा सकता है।
- 2.3. नमूना आकार:** सर्वेक्षण में शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण परिवारों के कुल 6,700 व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए शहरानुसार नमूना आकार का पालन किया जाना चाहिए। वर्तमान शहरानुसार नमूना आकार अनुलग्नक बी में दिया गया है। डीआईसीजीसी, अपने विवेक पर, बिना कोई कारण बताए नमूने के आकार को बढ़ा या घटा सकता है।
- 2.4. उत्तरदाताओं का प्रकार:** 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो की नमूना परिवार का सदस्य हो, जो या तो आय कमाने वाला सदस्य हो या घरेलू खर्चों के बारे में जानता हो और बैंकिंग के बारे में जानता हो।
- 2.5. डेटा संग्रह विधि:** एजेंसी को प्रत्येक शहर में चयनित परिवारों से CAPI (कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू) विधि का उपयोग करके व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करनी होगी। अचानक अपरिहार्य व्यवधानों के मामले में, एजेंसियों के पास टेलीफोनिक मोड (कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू (सीएटीआई) प्रणाली का उपयोग करके) या ऑनलाइन मोड के माध्यम से, बहुत कम सूचना पर सर्वेक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसा कि उस समय आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाए।
- 2.6. सर्वेक्षण प्रश्रावली:** सर्वेक्षण भारत में जमा बीमा के बारे में जनता की समझ का आकलन करेगा, डीआईसीजीसी के कामकाज और भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी समावेशी निर्देशों के तहत रखे गए परिसमापन बैंकों और बैंकों के मामले में दावा निपटान प्रक्रिया का आकलन करेगा। सर्वेक्षण प्रश्रावली अनुलग्नक ए में दी गई है।
- 2.7. समय अनुसूची:** डीआईसीजीसी सर्वेक्षण के लिए समय सारिणी प्रदान करेगा और एजेंसी को समय अनुसूची के अनुसार सर्वेक्षण कार्य पूरा करने की आवश्यकता होगी। सामान्यतः, सर्वेक्षण क्षेत्र कार्य 10 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए, जिसमें शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश भी सम्मिलित हैं।
- 2.8. एजेंसी को डीआईसीजीसी द्वारा आवश्यक फील्डवर्क, फील्ड पर्यवेक्षण और साक्षात्कार की प्रामाणिकता, गुणवत्ता जांच, डेटा जांच, कोडिंग, डेटा प्रविष्टि और सर्वेक्षण के डेटा सत्यापन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इनके अलावा, एजेंसी को निम्नलिखित प्रदान करने की आवश्यकता होगी:**
- 2.8.1 सभी साक्षात्कारों की पूर्ण और स्पष्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऑडियो-रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता अच्छे स्तर की हो। निगरानी के उद्देश्य से डेटा और ऑडियो रिकॉर्डिंग/फाइलें दैनिक आधार पर डीआईसीजीसी को (ऑनलाइन) उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

एक विशेष दिन में किए गए साक्षात्कारों को उसी दिन अपलोड किया जाना चाहिए और डीआईसीजीसी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2.8.2 साक्षात्कार के स्थान के लिए जीपीएस निर्देशांक को दर्ज किया जाना अनिवार्य है। निर्देशांक को एक हाइपरलिंक के साथ रखा जाना चाहिए, जो उपयोगकर्ता को मानचित्र पर समन्वय स्थान दिखाने वाले वेब पेज पर रीडायरेक्ट करता है, अधिमानतः गूगल मानचित्र पर। गलत स्थान वाले उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- 2.9. डीआईसीजीसी के पास आवश्यकता पड़ने पर कवरेज (राज्य, जिला और सर्वेक्षण स्थान जैसे शहरों, कस्बों और गांवों) या नमूना आकार, नमूना डिजाइन, सर्वेक्षण प्रश्नावली आदि को बदलने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित है।

3. डीआईसीजीसी द्वारा एजेंसी को प्रदान की गई सामग्री

डीआईसीजीसी सर्वेक्षण शुरू करने से पहले सर्वेक्षण के संचालन के लिए आवश्यक निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराएगा।

- 3.1. सर्वेक्षण कवरेज, नमूना आकार और नमूना डिजाइन
- 3.2. कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली की स्क्रिप्ट।
- 3.3. डीआईसीजीसी की ओर से उत्तरदाताओं से अपेक्षित जानकारी (डेटा) एकत्र करने के लिए एजेंसी को अधिकृत करने वाला एक पत्र (एजेंसियों को डीआईसीजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई पत्र जारी नहीं करना चाहिए)। एजेंसी को डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की गई 'मास्टर प्रतियों' का उपयोग करके प्राधिकरण पत्रों आदि की छपाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।
- 3.4. एमएस-एक्सेल प्रारूप में डेटा सबमिशन प्रारूप / संरचना।
- 3.5. फील्ड वर्क और सर्वेक्षण प्रश्नावली भरने के लिए दिशानिर्देश।
- 3.6. दोनों पक्षों, यानी डीआईसीजीसी और एजेंसी द्वारा निर्णय और पारस्परिक रूप से सहमत होने पर कोई अन्य सामग्री।

4. एजेंसी के कर्तव्य

- 4.1. एजेंसी यानी सफल बोलीदाता परियोजना के आवंटन के 05 दिनों के भीतर मुंबई में डीआईसीजीसी के साथ एक अनुबंध निष्पादित करेगा।

फील्ड वर्क के संदर्भ में

- 4.2. एजेंसी को समय पर सर्वेक्षण पूरा करने के लिए पर्याप्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ-साथ योग्य जांचकर्ताओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू

(‘सीएपीआई’) इंस्ट्रूमेंट (हार्डवेयर) को पर्याप्त संख्या में प्रासंगिक सॉफ्टवेयर के साथ सर्वेक्षण कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे एजेंसी द्वारा जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण के साथ-साथ फील्ड वर्क के लिए भी व्यवस्थित / खरीदा जाना चाहिए। डीआईसीजीसी इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और इसके लिए डीआईसीजीसी द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- 4.3. एजेंसी को प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में परिवारों का साक्षात्कार करके प्रश्नावली में निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होगी। एजेंसी को सीएपीआई प्रणाली के लिए अनुसूची/प्रश्नावली विकसित करने, डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद करने और डीआईसीजीसी द्वारा जांच के लिए भेजने की आवश्यकता होगी।
- 4.4. **फील्ड वर्क करने वाले जांचकर्ताओं के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता (मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित की जा सकती है) स्नातक है**, अधिमानतः अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / गणित के साथ एक विषय के रूप में। फील्ड सुपरवाइजर/कोऑर्डिनेटर के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उन्हें उसी फील्ड में पर्याप्त प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जांचकर्ताओं और उनके पर्यवेक्षक को डीआईसीजीसी द्वारा मुंबई स्थित डीआईसीजीसी कार्यालय में आयोजित ब्रीफिंग/प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है, जिसकी कोई लागत डीआईसीजीसी पर नहीं आएगी, और यह सर्वेक्षण के क्षेत्र कार्य शुरू होने से पहले होना चाहिए।
- 4.5. एजेंसी को डीआईसीजीसी द्वारा प्रशिक्षण के लिए उचित शैक्षिक योग्यता और अन्य कौशल के साथ पर्याप्त संख्या में जांचकर्ताओं को लाने की आवश्यकता होगी। इससे डीआईसीजीसी को सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण जांचकर्ताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। **डीआईसीजीसी किसी भी पर्यवेक्षक/अन्वेषक को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह उपयुक्त नहीं पाया जाता है।**
- 4.6. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि केवल वे जांचकर्ता जिन्होंने विशिष्ट दौर के लिए डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था, फील्ड वर्क करें। एक विशेष दिन पर सर्वेक्षण के लिए तैनात किए गए जांचकर्ताओं को एक साथ कोई अन्य सर्वेक्षण कार्य या कोई अन्य लाभकारी कार्य करने की अनुमति नहीं है।
- 4.7. डीआईसीजीसी जांचकर्ताओं को निःशुल्क एक दौर का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। डीआईसीजीसी द्वारा जांचकर्ताओं को कोई भी अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रभाष्य है (पैरा 7.2.3 देखें)।
- 4.8. एजेंसी को अनुलग्नक बी में दिए गए अनुसार प्रत्येक केंद्र/शहर के लिए जांचकर्ताओं की न्यूनतम निर्धारित संख्या की तैनाती सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी बदलाव के मामले में, जांचकर्ताओं की न्यूनतम संख्या के बारे में डीआईसीजीसी द्वारा एजेंसी को सूचित किया जाएगा। हालांकि, यदि

आवश्यक हो, तो एजेंसी को समय पर सर्वेक्षण पूरा करने के लिए जांचकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की स्थिति में होना चाहिए।

- 4.9.** एजेंसी को प्रत्येक केंद्र के लिए प्रति राउंड प्रति जांचकर्ता अधिकतम कॉल / साक्षात्कार की अनुमति का सख्ती से पालन करना होगा। निर्धारित सीमा से ऊपर किसी भी कॉल / साक्षात्कार को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 4.10.** डीआईसीजीसी द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी की उचित देखरेख में फील्डवर्क किया जाना चाहिए।
- 4.11.** एजेंसी को डीआईसीजीसी को जमा करने से पहले डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से/संपूर्ण गुणवत्ता जांच (यानी, शुद्धता, स्थिरता, डेटा प्रविष्टि, कोडिंग, आदि) करनी चाहिए। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाए और किसी भी चूक को गंभीरता से देखा जाएगा (उप शीर्षक 7 देखें - एजेंसी का प्रदर्शन और नुकसान, यदि कोई हो)।
- 4.12.** शहर-वार आंकड़ों की जांच करने के बाद, एजेंसी प्रत्येक शहर की गैर-प्रतिक्रिया जानकारी सहित पूरे शहर-वार सर्वेक्षण डेटा को डीआईसीजीसी को प्रस्तुत करेगी। डीआईसीजीसी फील्ड सत्यापन (कम से कम 5%) के साथ-साथ ऑनसाइट/टेलीफोनिक सत्यापन (कम से कम 5%) के माध्यम से भरे हुए अनुसूचियों में डेटा की गुणवत्ता और सटीकता की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। फील्ड सत्यापन के समय, एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्वेक्षण करने वाले संबंधित अन्वेषक को प्रतिवादी की पहचान के लिए डीआईसीजीसी अधिकारियों के साथ जाना आवश्यक होगा। एजेंसी को दंडित किया जाएगा, यदि अन्वेषक क्षेत्र सत्यापन के दौरान डीआईसीजीसी अधिकारियों के साथ नहीं जाता है (पैरा 7.2.4)। साथ ही, डीआईसीजीसी उन जांचकर्ताओं द्वारा किए गए सभी साक्षात्कारों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 4.13.** डेटा में किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित अन्वेषक से संबंधित आंशिक/पूरी जानकारी को खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, डीआईसीजीसी ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है (उप शीर्षक देखें 7 - एजेंसी का प्रदर्शन और जुर्माना, यदि कोई हो)। **फर्जी कॉल, खराब डेटा गुणवत्ता आदि जैसे चरम परिदृश्यों में, डीआईसीजीसी अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**
- 4.14.** साक्षात्कार की समाप्ति तब हो सकती है जब उत्तरदाता प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 और 4 के उत्तर में अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं (अनुलग्नक देखें)। इस तरह के बंद किए गए साक्षात्कारों को आंशिक साक्षात्कार के रूप में माना जाएगा। एक सफल

साक्षात्कार को प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के व्यापक समापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो गुणवत्ता आश्वासन के साथ सभी आवश्यक जानकारी के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। इस सर्वेक्षण के लिए लक्षित नमूना आकार 6,700 है। एजेंसी कम से कम 6,200 सफल साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए बाध्य है, जिसके लिए उन्हें प्रति साक्षात्कार पूरी अनुबंधित राशि प्राप्त होगी। आंशिक साक्षात्कार के लिए मुआवजा कम दर पर होगा यानी प्रति सफल साक्षात्कार उद्धृत राशि का 30%। आंशिक साक्षात्कार की कुल संख्या, कम दर पर भुगतान के लिए पात्र, 500 से अधिक नहीं होगी।

डेटा प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में

- 4.15. सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, एजेंसी को सर्वेक्षण के प्रत्येक दौर को शुरू करते समय दी गई तारीख को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप और फ़ाइल प्रकार के अनुसार डीआईसीजीसी को सॉफ्ट कॉपी में डेटा प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, एजेंसी द्वारा डीआईसीजीसी को निम्नलिखित आउटपुट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- 4.15.1. **दैनिक पर्यवेक्षी रिपोर्ट:** एजेंसी को सर्वेक्षण की निगरानी की सुविधा के लिए उक्त उद्देश्य के लिए एजेंसी द्वारा डिज़ाइन किए गए डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक आधार पर विस्तृत डेटा और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ डीआईसीजीसी को निर्दिष्ट तालिकाएं (अनुलग्नक-सी) प्रदान करनी चाहिए।
- 4.15.2. **दैनिक डेटा:** एजेंसी को वास्तविक समय के आधार पर ऑडियो रिकॉर्डिंग/फाइलों के साथ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डेटा भी प्रस्तुत करना चाहिए।
- 4.15.3. **स्वरूपित और पूर्ण डेटाबेस:** एजेंसी को सर्वेक्षण के प्रत्येक दौर के दौरान इंगित निर्धारित समय में, निर्धारित डेटा गुणवत्ता जांच के बाद निर्धारित प्रारूप (डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए अनुलग्नक डी) में पूर्ण ऑडियो फाइल के साथ अंतिम डेटा डीआईसीजीसी को प्रस्तुत करना चाहिए। अंतिम डेटा में प्रतिक्रियाओं की संख्या प्रत्येक मतदान केंद्र के साथ-साथ प्रत्येक सर्वेक्षण केंद्र के लिए लक्षित नमूना आकार के भीतर होनी चाहिए, और एजेंसी द्वारा प्रचारित किसी भी अतिरिक्त कॉल को अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह डीआईसीजीसी का एकमात्र विवेकाधिकार होगा कि वह उन अतिरिक्त कॉलों को स्वीकार या अस्वीकार करे।
- 4.15.4. **स्थानीय जानकारी:** एजेंसी को प्रत्येक अन्वेषक के लिए डीआईसीजीसी को कम से कम एक दिन पहले तिथि-वार क्षेत्र आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि डीआईसीजीसी को किसी भी समय ऑन-स्पॉट सत्यापन की निगरानी और संचालन करने में सक्षम बनाया जा सके। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस स्थान के जीपीएस निर्देशांक जहां साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं, सटीक रूप से कैप्चर किए जाते हैं।

जीपीएस निर्देशांक को पकड़ने में विफलता को गंभीरता से देखा जाएगा और डीआईसीजीसी उन साक्षात्कारों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जीपीएस निर्देशांक डेटा के गुम होने की बार-बार घटना पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

4.15.5. **गुणवत्ता जांच:** एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीआईसीजीसी को सौंपे किए गए डेटा की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। एजेंसी द्वारा की गई गुणवत्ता जांच का विवरण और साक्षात्कारवार टिप्पणियों को दैनिक आधार पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीआईसीजीसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें इस प्रक्रिया के माध्यम से अस्वीकृत साक्षात्कारों की सूची भी शामिल है। एजेंसी को डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की गई निरंतरता जांच के अनुसार साक्षात्कार के भीतर प्रतिक्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए।

4.15.6. **ऑडियो रिकॉर्ड:** एजेंसी को जांचकर्ताओं को साक्षात्कार की उचित ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश देना चाहिए। इसके अलावा, एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी साक्षात्कारों के स्पष्ट रूप से श्रव्य ऑडियो-रिकॉर्ड सत्यापन के लिए डीआईसीजीसी को दैनिक आधार पर उपलब्ध कराए जाएं।

4.15.7. **गैर-प्रतिक्रिया:** गैर-प्रतिक्रिया देने वाले परिवारों का विवरण अनुरोध किए जाने पर कारणों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. सर्वेक्षण की समय सारिणी

5.1. यह सर्वेक्षण एक बार की कवायद के रूप में किया जाएगा, जो अनुबंध के निष्पादन से एक से दो महीने बाद शुरू होगा।

5.2. एजेंसी को डीआईसीजीसी द्वारा सूचित समय सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए और निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कार्य पूरा करना चाहिए। संभावित समय सारिणी इस प्रकार है:

गतिविधियाँ	समय सारिणी
एजेंसी को प्री-लॉन्च जानकारी	लॉन्च से कम से कम पाँच दिन पहले
अन्वेषक का प्रशिक्षण	सर्वेक्षण क्षेत्र कार्य शुरू होने से एक या दो दिन पहले
क्षेत्र कार्य का शुभारंभ और सर्वेक्षण	आम तौर पर सर्वेक्षण फील्डवर्क के लिए 10 दिन दिए जाएंगे जिसमें शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। अंतिम डेटा प्रस्तुत करने के बाद, डेटा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर अस्वीकृति के

	<p>मामले में फ़ील्डवर्क को फिर से संचालित करने के लिए एजेंसी को 4 दिनों (अतिरिक्त अवधि) की अवधि दी जा सकती है। यह डीआईसीजीसी के विवेक पर होगा और नुकसान को आकर्षित करेगा (पैरा 7.2.7 देखें)।</p> <p>सर्वेक्षण अवधि की वास्तविक तिथियों को ई-मेल और/या लॉन्चिंग पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।</p>
एजेंसी द्वारा डीआईसीजीसी को अंतिम डेटा प्रस्तुत करना	सर्वेक्षण क्षेत्र के काम के बंद होने के 2 दिनों के भीतर, जिसमें शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं।
फ़ील्ड सत्यापन (एक अन्वेषक के लिए)	डीआईसीजीसी द्वारा एजेंसी को एक दिन पूर्व सूचना के साथ अंतिम डेटा प्रस्तुत करने के बाद डीआईसीजीसी के विवेक पर किसी भी दिन।

5.3. सर्वेक्षण शुरू करते समय छोटे नमूने वाले केंद्रों के लिए समय सारिणी दी जाएगी।

6. बयाना जमाराशि

6.1. एजेंसी को बयाना जमाराशि (ईएमडी) के रूप में ₹ 35,510 की राशि जमा करने की आवश्यकता है। बोलीदाताओं को बैंक गारंटी ('बीजी')/एनईएफटी (भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के पक्ष में) के माध्यम से अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी ई-खरीद <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/> पोर्टल में खाता संख्या 8705688 और आईएफएससी - DICG0000002 (5वें से 10वें अक्षर शून्य हैं) के माध्यम से ईएमडी की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। ईएमडी की वैधता (अधिमानत: बैंक गारंटी के रूप में) जारी होने की तारीख से छह महीने तक होगी। ईएमडी की मूल हार्डकॉपी बोलियां खोलने से पहले संचार के पते पर पहुंच जानी चाहिए। ऐसी बोली जिसके साथ ऐसी ईएमडी नहीं है, उस पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। वित्तीय बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईएमडी को डीआईसीजीसी द्वारा एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा। निम्नलिखित परिदृश्यों में EMD की राशि जब्त कर ली जाएगी:

- i. यदि बोलीदाता बिना कोई संतोषजनक कारण बताए बोली की वैधता अवधि से पहले बोली वापस ले लेता है;
- ii. यदि सफल बोलीदाता बिना किसी संतोषजनक कारण के इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुबंध को स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने में विफल रहता है;

- iii. यदि चयनित बोलीदाता बिना किसी संतोषजनक कारण के करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने में विफल रहता है।

6.2. बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह ईएमडी बिना किसी ब्याज के असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता (चयनित एजेंसी) के लिए, ईएमडी केवल निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने पर ही वापस किया जाएगा, जैसा कि अनुबंध में निर्धारित किया जा सकता है।

7. एजेंसी का प्रदर्शन और जुर्माना, यदि कोई हो

7.1. एजेंसी को प्रो-फॉर्मा (अनुलग्नक एफ) के अनुसार, वार्षिक अनुबंध के कुल उद्धृत मूल्य के न्यूनतम 05 प्रतिशत की राशि के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसकी वैधता डीआईसीजीसी की संतुष्टि के लिए अनुबंध के पूरा होने के 6 महीने तक है। विकल्प में, डीआईसीजीसी वाक्यांश 'जो भी पहले हो' को 'जो भी बाद में हो' में संशोधित कर सकता है। आगे की अवधि के लिए अनुबंध के नवीनीकरण के मामले में, एजेंसी को नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

7.2. समय को अनुबंध का एक आवश्यक अंग माना जाएगा और एजेंसी को सर्वेक्षण की समयसीमा का पालन करना आवश्यक होगा। अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के निष्पादन/निष्पादन में एजेंसी की ओर से कोई भी देरी डीआईसीजीसी को निम्नलिखित कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगी:

7.2.1. एजेंसी को सर्वेक्षण क्षेत्र के कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए, जिसे सर्वेक्षण शुरू करते समय सूचित किया गया था। हालांकि, यदि समय अनुसूची के अनुसार एक या एक से अधिक शहरों/शहरों के लिए लक्षित नमूना आकार प्राप्त नहीं किया जाता है, तो एजेंसी, डीआईसीजीसी से उचित अनुमति के साथ, नमूना आकार प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का काम जारी रख सकती है और सर्वेक्षण फील्डवर्क के अंत से अगले दिन के अंत तक ('ईओडी') अंतिम डेटा (कोई आंशिक डेटा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है) प्रस्तुत कर सकती है। उस स्थिति में, विस्तारित अवधि के लिए एजेंसी पर प्रति दिन ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में, 2 दिनों से अधिक के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 7.2.2. अंतिम डेटा प्रस्तुत करने में 10 दिनों से अधिक की देरी के मामले में (कोई आंशिक डेटा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है), एजेंसी को देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये केवल) का जुर्माना देना होगा, जो पूरी तरह से एजेंसी के कारण होगा।
- 7.2.3. डीआईसीजीसी द्वारा जांचकर्ताओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए, प्रति प्रशिक्षण प्रति केंद्र एजेंसी से 7,000/- रुपये की राशि ली जाएगी।
- 7.2.4. फील्ड सत्यापन के लिए डीआईसीजीसी अधिकारियों के साथ जाने में विफल रहने वाले जांचकर्ताओं के मामले में, एजेंसी पर प्रति जांचकर्ता 5000/- रुपये की राशि लगाई जाएगी। यह ऐसे अन्वेषक द्वारा किए गए साक्षात्कारों की अस्वीकृति के अतिरिक्त होगा।
- 7.2.5. डेटा में किसी भी विसंगति के मामले में, आंशिक/संपूर्ण लॉट को अस्वीकार किया जा सकता है। यदि किसी विशेष अन्वेषक द्वारा किए गए साक्षात्कारों में ऐसी विसंगतियां पाई जाती हैं/दोहराई जाती हैं, तो उसे सर्वेक्षण के प्रचार से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह की विसंगतियों की पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो सकता है।
- 7.2.6. एजेंसी को प्रति अनुसूची पूर्ण भुगतान के लिए गुणवत्ता जांच लागू करने के बाद, शहरवार न्यूनतम 85% नमूना आकार और समग्र रूप से न्यूनतम 90% नमूना आकार प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा, एजेंसी को कम दर पर भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, प्रति अनुसूची उद्धृत राशि का 90%। इस मामले में, डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा।
- 7.2.7. अतिरिक्त अवधि के दौरान किए गए कॉल / साक्षात्कार के लिए, एजेंसी को कम दर पर भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, प्रति अनुसूची राशि का 85%।
- 7.2.8. फर्जी साक्षात्कार के मामले में, संबंधित अन्वेषक द्वारा किए गए पूरे या आंशिक कार्य को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे अन्वेषक को भविष्य में सर्वेक्षण के किसी भी दौर में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस तरह की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, डीआईसीजीसी के विवेक पर, अनुबंध समाप्त हो सकता है।
- 7.2.9. यदि चयनित एजेंसी काम करने में विफल रहती है, या गुणवत्ता और समयबद्धता के मामले में डीआईसीजीसी की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है, तो डीआईसीजीसी असफल एजेंसी के जोखिम और लागत पर किसी अन्य सूचीबद्ध एजेंसी को काम देने के लिए स्वतंत्र होगा। अनुबंध को समाप्त करने के अलावा, डीआईसीजीसी वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी संबंधित एजेंसी को पैनल से हटाने के साथ-साथ डीआईसीजीसी की किसी भी

परियोजना को शुरू करने से प्रतिबंधित करने/हटाने का भी निर्णय ले सकता है। इसके अलावा, डीआईसीजीसी, इस दस्तावेज़ के तहत अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खरीद आदेश मूल्य से कटौती करता है, परिसमापन क्षति के रूप में, देरी के प्रत्येक कैलेंडर दिन के लिए कुल विचार राशि के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि, जिसकी अधिकतम सीमा कुल खरीद आदेश मूल्य का 10 प्रतिशत है। इस तरह के जुर्माने को बोलीदाता के बिलों से या बैंक गारंटी के आह्वान से काटा जाएगा। डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।

8. दस्तावेज़ और डेटा का स्वामित्व

एजेंसी इस बात से सहमत होगी कि सर्वेक्षण के दौरान उत्पन्न, एकत्र या उत्पादित सभी दस्तावेजों और डेटा के संबंध में स्वामित्व, कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार डीआईसीजीसी की अनन्य संपत्ति होगी और एजेंसी का ऐसे दस्तावेजों या डेटा पर कोई दावा या शीर्षक नहीं होगा।

9. सूचना की गोपनीयता

9.1. एजेंसी इस खंड में निर्धारित दायित्वों का पालन करने और व्यक्तिगत डेटा की अत्यधिक गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लागू डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करने के लिए सहमत है।

9.1.1. गोपनीयता का दायित्व: सर्वेक्षण एजेंसी स्वीकार करती है और सहमत है कि, सर्वेक्षण के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के दौरान, जैसा कि सफल एजेंसी के साथ निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध के तहत निर्धारित किया जा सकता है, यह व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी ("व्यक्तिगत डेटा") एकत्र कर सकता है, अभिगम कर सकता है या संसाधित कर सकता है। एजेंसी ऐसी सभी सूचनाओं को पूरी तरह से गोपनीय मानेगी और लागू डेटा संरक्षण कानूनों [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम"), और डीपीडीपी नियम, 2025 (जब भी लागू होगी)] के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए या जारी किए जाने वाले किसी भी लागू नियम, विनियम या दिशानिर्देश का पालन करेगी।

9.1.2. संग्रह और उपयोग: एजेंसी केवल उन उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करेगी जो डीआईसीजीसी द्वारा सर्वेक्षण के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा संग्रह वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी है। एजेंसी अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के

लिए आवश्यक सीमा तक ही व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करेगी और किसी भी अनधिकृत उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग नहीं करेगी।

- 9.1.3. सुरक्षा और सुरक्षा: एजेंसी व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण, परिवर्तन, विनाश या हानि से बचाने के लिए उचित तकनीकी, संगठनात्मक और सुरक्षा उपायों को लागू और बनाए रखेगी। ये उपाय लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन में होंगे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन होंगे।
- 9.1.4. व्यक्तिगत डेटा का प्रकटीकरण: एजेंसी डीआईसीजीसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ व्यक्तिगत डेटा का खुलासा या साझा नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जहां कानून द्वारा आवश्यक हो या न्यायिक/वैधानिक/सरकारी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में हो।
- 9.1.5. अभिगम नियंत्रण: व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच एजेंसी के अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होगी, जिन्हें इस समझौते के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस तरह की पहुंच की आवश्यकता होती है। ऐसे सभी कर्मियों को सख्त गोपनीयता दायित्वों से बांधा जाएगा और लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 9.1.6. प्रतिधारण और निपटान: एजेंसी व्यक्तिगत डेटा को केवल तब तक बनाए रखेगी जब तक कि यह उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था या लागू कानून के तहत आवश्यक है। परियोजना के पूरा होने या इस समझौते की समाप्ति पर, एजेंसी डीआईसीजीसी द्वारा निर्देशित सभी व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रूप से नष्ट कर देगी या वापस कर देगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई अवशिष्ट प्रतियां न रहें।
- 9.1.7. उल्लंघन अधिसूचना: व्यक्तिगत डेटा से जुड़े किसी भी वास्तविक या संदिग्ध डेटा उल्लंघन की स्थिति में, एजेंसी तुरंत डीआईसीजीसी और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (डीपीडीपी अधिनियम के तहत स्थापित होने पर) को सूचित करेगी और उल्लंघन के प्रभाव को कम करने, इसके कारण की जांच करने और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने में पूरी तरह से सहयोग करेगी।
- 9.1.8. क्षतिपूर्ति: एजेंसी एजेंसी द्वारा इस गोपनीयता खंड के उल्लंघन या लागू डेटा सुरक्षा कानूनों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, क्षति या दंड के खिलाफ हानिरहित डीआईसीजीसी की क्षतिपूर्ति करेगी और उसे धारण करेगी।

9.1.9. लेखा परीक्षा और निगरानी: डीआईसीजीसी अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय एजेंसी की डेटा सुरक्षा प्रथाओं और इस खंड के अनुपालन का ऑडिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9.1.10. उत्तरजीविता: इस गोपनीयता खंड के तहत दायित्व अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति तक जीवित रहेंगे।

10. एजेंसी द्वारा उपक्रम

10.1. एजेंसी डीआईसीजीसी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी भी संगठन, व्यक्ति, फर्म या उसके फ्रेंचाइजी को सर्वेक्षण फील्डवर्क का उप-अनुबंध नहीं करेगी; यह एजेंसी के कर्मियों के अलावा किसी अन्य को डीआईसीजीसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना डीआईसीजीसी के लिए एजेंसी द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं देगा।

10.2. डीआईसीजीसी की अनुमति से किसी भी उप-ठेकेदार की नियुक्ति, यदि कोई हो, एजेंसी को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगी और एजेंसी अनुबंध के तहत सभी दायित्वों के प्रदर्शन और पूरा करने के लिए डीआईसीजीसी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगी।

10.3. इस घटना में कि एजेंसी सामान्य पाठ्यक्रम में व्यवसाय करना बंद कर देती है या दिवालियापन से संबंधित किसी भी देश या राज्य के किसी भी अधिनियम या क़ानून के तहत किसी भी कार्यवाही के अधीन हो जाती है या इसका लाभ उठाती है या उसके अधीन हो जाती है, एजेंसी के साथ अनुबंध तुरंत, समाप्त हो जाएगा और कोई और बल या प्रभाव नहीं होगा और किसी भी पक्ष की कोई संपत्ति या अधिकार, मूर्त या अमूर्त, तुरंत इसे वापस कर दिया जाएगा।

10.4. एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह डीआईसीजीसी द्वारा समय-समय पर उठाए जाने वाले सभी प्रश्नों/शिकायतों का तुरंत उत्तर देगी। एजेंसी द्वारा टालमटोल करने वाले रवैये को "असंतोषजनक प्रदर्शन" के रूप में माना जाएगा और अनुबंध के नवीनीकरण के समय डीआईसीजीसी द्वारा इसे ध्यान में रखा जाएगा।

10.5. एजेंसी द्वारा कोई भी प्रचार जिसमें निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के नाम का उपयोग किया जाना है, केवल डीआईसीजीसी की स्पष्ट लिखित अनुमति के साथ किया जाना चाहिए।

10.6. एजेंसी देश के सभी लागू कानूनों और विभिन्न नियामक, वैधानिक और सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित 'नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों' का पालन करेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अन्य श्रम कानून और लागू डेटा संरक्षण कानून शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। एजेंसी किसी भी दावे या मांग, कार्रवाई या कार्यवाही से डीआईसीजीसी को क्षतिपूर्ति करेगी,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क़ानून, नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप या उत्पन्न होने वाली किसी भी क़ानून, नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों, और अनुबंध के साथ-साथ भी।

- 10.7.** एजेंसी यह वचन देती है कि दायित्वों को पूरा करने में, एजेंसी भारत में लागू सभी लागू कानूनों, संहिताओं, नियमों, निर्देशों और अधिसूचनाओं आदि का पालन करेगी। डीआईसीजीसी को एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कानून के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

11. भुगतान की शर्तें

- 11.1.** सर्वेक्षण फील्डवर्क के लिए एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी भुगतान सर्वेक्षण फील्डवर्क के पूरा होने के बाद ही किए जाएंगे, बशर्ते कि उपरोक्त नियमों और शर्तों का पालन करते हुए डीआईसीजीसी पूरी तरह से संतुष्ट हो।
- 11.2.** भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा स्वीकार की गई प्रतिक्रियाओं की संख्या के अनुसार किया जाएगा। गुणवत्ता जांच में नकली कॉल को हटाना शामिल है (उदाहरण के लिए, एक प्रशिक्षित अन्वेषक के नाम पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए साक्षात्कार, वास्तव में साक्षात्कार नहीं किए गए आदि), निर्दिष्ट संख्या से अधिक कॉल। प्रति मतदान केंद्र कॉल की संख्या, निर्दिष्ट संख्या से अधिक कॉल करें। प्रति अन्वेषक प्रति दिन कॉल, अप्रशिक्षित जांचकर्ताओं की कॉल, आदि। एजेंसी को प्रति शेड्यूल पूर्ण भुगतान के लिए गुणवत्ता जांच लागू करने के बाद, न्यूनतम 85% नमूना आकार शहर-वार और न्यूनतम 90% नमूना आकार प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा, एजेंसी को कम दर पर भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, प्रति अनुसूची उद्धृत राशि का 90%। इस मामले में, डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.3.** यदि किसी शहर के लिए स्वीकृत अनुसूचियों की संख्या 85% से कम है, तो डीआईसीजीसी एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगेगा और चयनित एजेंसी के साथ अनुबंध को समाप्त करने और दोहराए जाने वाले घटना के मामले में परियोजना को किसी अन्य एजेंसी को प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 11.4.** **एजेंसी द्वारा जांचकर्ताओं को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक:** एजेंसी को जांचकर्ताओं को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा। प्रति अनुसूची / साक्षात्कार के लिए 175 / – रुपये की न्यूनतम राशि और प्रति दिन 290 / – प्रति दिन का न्यूनतम दैनिक भत्ता (यात्रा व्यय सहित) एक अन्वेषक को भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही एजेंसी पर डीआईसीजीसी द्वारा लगाए गए किसी भी दंड के बावजूद। यह इस दस्तावेज के पैरा 10.6 के तहत एजेंसी के दायित्व के अतिरिक्त होगा, अर्थात्, एजेंसी भूमि के सभी लागू कानूनों और विभिन्न नियामक, वैधानिक और

सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित 'नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों' का पालन करेगी, जैसे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य श्रम कानून।

- 11.5.** निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के संबंध में कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा:
- जिसके लिए भरा हुआ सीएपीआई डेटा प्रस्तुत नहीं किया जाता है क्योंकि या तो परिवार उपलब्ध नहीं हैं या किसी अन्य कारण से उत्तर देने से इनकार करते हैं।
 - जो डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार अधूरा है या भरा नहीं गया है
 - जहां डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्ट रूप में डेटा नहीं पाया जाता है।
 - यदि डीआईसीजीसी द्वारा सत्यापन के बाद पूरी भरी हुई सर्वेक्षण प्रश्नावली फर्जी पाई जाती है।
- 11.6.** हालांकि डीआईसीजीसी को प्रस्तुत अधूरी अनुसूचियों के संबंध में पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा, एजेंसी को उन गैर-प्रतिक्रियाओं के बारे में एक स्थिति-रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह गैर-प्रतिक्रियाओं पर जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से है। इस रिपोर्ट के लिए कोई शुल्क/शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- 11.7.** किसी भी स्थान पर आउटसोर्सिंग कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी द्वारा नियोजित या नियोजित संसाधन व्यक्तियों के वेतन, मजदूरी, भत्ते, आवास के लिए भुगतान, परिवहन आदि सहित अनुबंध के तहत परिकल्पित फील्ड वर्क और डेटा टेबुलेशन कार्य के लिए एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी अन्य खर्च, सरकार को कर, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले आदि का पूरी तरह से भुगतान/पूर्त/वहन केवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- 11.8.** आयकर अधिनियम की धारा 194सी के प्रावधानों के अनुसरण में, डीआईसीजीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह डीआईसीजीसी को सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुबंध के तहत देय राशि पर लागू दर पर कर की कटौती करे। यदि एजेंसी द्वारा लागू कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो एजेंसी द्वारा संबंधित आयकर अधिकारी से छूट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। डीआईसीजीसी बिल से किसी भी अन्य कर की कटौती करेगा जो भुगतान करते समय लागू हो सकता है।
- 11.9.** डीआईसीजीसी कोई कर (सीजीएसटी और एसजीएसटी को छोड़कर) वहन नहीं करेगा और न तो किसी भी कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा और न ही टीडीएस के अधीन होगा।

11.10. सभी भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा केवल मुंबई में, भारतीय रुपये में, एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट खाते में किए जाएंगे। अनुबंध से उत्पन्न होने वाले भुगतान के उद्देश्य से खाता संख्या में कोई भी परिवर्तन एजेंसी द्वारा डीआईसीजीसी को लिखित रूप में तुरंत सूचित किया जाएगा।

12. प्रशासकीय भाषा

सफल बोलीदाता के साथ निष्पादित अनुबंध मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के प्रावधानों का पालन करने के लिए द्विभाषी रूप में (हिंदी में अनुवाद के माध्यम से) हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाएगा। अनुबंध के अंग्रेजी और हिंदी ग्रंथों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा। अनुबंध के तहत आवश्यक सभी नोटिस, पत्राचार, सूचना, साहित्य, डेटा, मैनुअल, प्रक्रियाएं और अन्य दस्तावेज केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।

13. मध्यस्थता

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम और एजेंसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे बातचीत और आपसी चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की बातचीत शुरू होने के तीस (30) दिनों के बाद, डीआईसीजीसी और एजेंसी सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को हल करने में असमर्थ रहे हैं, कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से विशिष्ट विवाद और/या मतभेदों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिस पर मध्यस्थता की आवश्यकता है। इस तरह के विवाद और/या अंतर को पारस्परिक रूप से सहमत एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। ऐसी कोई भी मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इस संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मुकदमे, कार्यवाही, कार्यवाही, विवाद और किसी भी प्रकार के मतभेद केवल मुंबई में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। मध्यस्थता का स्थान और स्थान मुंबई, भारत होगा।

14. समाप्ति

14.1. किसी भी पक्ष को इस मामले में दूसरे पक्ष को एक महीने पहले लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी पक्ष द्वारा और किसी भी कारण से अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, डीआईसीजीसी केवल अनुबंध के तहत देय पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए एजेंसी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हैं, पैरा 4, 7, 8 के प्रावधानों के अधीन, 9, 10 और 11 के ऊपर और एजेंसी अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसमें अनुबंध के तहत डीआईसीजीसी को सामग्री (जैसे एकत्र किए गए डेटा, आदि, इस तरह की समाप्ति की तारीख तक) सौंपना शामिल है।

- 14.2.** डीआईसीजीसी सर्वेक्षण में ऑडियो, टेलीफोनिक, ऑन-स्पॉट और फील्ड सत्यापन के माध्यम से एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता की जांच करेगा। यदि चयनित एजेंसी सर्वेक्षण डेटा की गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रतिक्रिया दर के संदर्भ में डीआईसीजीसी की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है, तो डीआईसीजीसी चयनित एजेंसी के साथ अनुबंध को समाप्त करने और विफल एजेंसी के जोखिम, व्यय और लागत पर किसी अन्य एजेंसी को परियोजना प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही, डीआईसीजीसी इसके लिए कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.3.** अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, पूर्ण या आंशिक रूप से, डीआईसीजीसी वैकल्पिक स्रोतों से सीएपीआई आधारित सर्वेक्षण करने के लिए स्वतंत्र है, जो एजेंसी द्वारा अवितरित/अनिष्पादित के समान है और उस स्थिति में, एजेंसी मूल्य अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 14.4.** हालांकि, अनुबंध की समाप्ति तक, यदि डीआईसीजीसी द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो एजेंसी अनुबंध के अनुसार भुगतान पर सेवाओं का विस्तार करने के लिए बाध्य होगी।
- 14.5.** किसी भी सर्वेक्षण के संबंध में अनुबंध की समाप्ति, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, एजेंसी को किसी भी अन्य जीवित संविदात्मक दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी।
- 14.6.** किसी भी स्तर पर, किसी परियोजना को सौंपना या अनुबंध को बंद करना डीआईसीजीसी के विवेक पर होगा और डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के संबंध में इसकी संतुष्टि के अधीन होगा। अनुबंध के आवंटन या समाप्ति के मामले में डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा। अनुबंध की समाप्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा और डीआईसीजीसी किसी भी लागत या क्षति या समाप्ति के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि कोई हो।

15. अपरिहार्य घटना

- 15.1.** "अपरिहार्य घटना" में पार्टियों के नियंत्रण से परे एक घटना, परिस्थिति या स्थिति शामिल होगी, जिसमें एक घटना, परिस्थिति या स्थिति शामिल है जो आग, बाढ़, बिजली की विफलता, ईश्वर के कार्यों, सार्वजनिक शत्रु के कार्यों, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, युद्ध, विद्रोह, दंगे, आतंकवादी हमले, श्रमिक अशांति, हड़ताल, तालाबंदी, गो-स्लो, दुर्घटनाओं के कारण मशीनरी को नुकसान या पात्र प्राधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा किसी वैधानिक आदेश के पारित होने के कारण होती है। डीआईसीजीसी को माल या प्रौद्योगिकी के निर्यात को प्रभावित करने वाले किसी भी देश के ऐसे दायित्व और प्रतिबंध या भारत के आयात नियम या आवश्यकताएं, जो भी कारण हैं, जो सर्वेक्षण के संचालन को प्रभावित करेंगे। हालांकि, इसमें एजेंसी की डिफ़ॉल्ट या लापरवाही या लापरवाही या

एजेसी की ओर से किसी कार्य के उचित परिणामों का आकलन करने में विफलता शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

- 15.2.** यदि किसी भी पक्ष को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपरिहार्य घटना के कारणों से रोका जाता है, जो उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर है, तो प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को अपरिहार्य घटना की घटना की घटना के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा अपरिहार्य घटना की घटना की तारीख से दस दिनों के भीतर।
- 15.3.** प्रभावित पक्ष इस तरह की अपरिहार्य घटना (घटनाओं) की घटना के कारण अनुबंध के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में किसी भी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यहां तक कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी।
- 15.4.** दोनों पक्ष अनुबंध के तहत दायित्वों को उचित परिश्रम के साथ पूरा करना जारी रखेंगे, जहां तक उन्हें उचित रूप से किया जा सकता है और अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और अपरिहार्य घटना की घटना से प्रभावित दायित्वों के प्रदर्शन और पूरा करने के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेंगे।
- 15.5.** कोई भी पक्ष ऐसे सभी संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन और समापन को फिर से शुरू करेगा, जैसा कि अपरिहार्य घटना से प्रभावित हो सकता है, जितनी जल्दी संभव हो, इस तरह की घटना समाप्त होने या अस्तित्व में समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करने के बाद और जारी किए गए निर्देशों के अधीन।
- 15.6.** यदि अपरिहार्य घटना साठ (60) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए जारी रहती है, तो अनुबंध के प्रदर्शन की निरंतरता की समीक्षा दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी और डीआईसीजीसी ऐसी स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 15.7.** यदि अनुबंध अपरिहार्य घटना की घटना से समाप्त हो जाता है, तो भुगतान किए गए अनुबंध के हिस्से के अनुरूप होगा।

16. यौन उत्पीड़न

- 16.1.** एजेसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। डीआईसीजीसी के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, एजेसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और एजेसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

- 16.2.** डीआईसीजीसी के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी/कर्मचारियों/कर्मियों की ओर से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का डीआईसीजीसी द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- 16.3.** एजेंसी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी, जिसे एजेंसी के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए डीआईसीजीसी के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
- 16.4.** एजेंसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित विषयों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- 16.5.** एजेंसी अपने उन कर्मचारियों आदि की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगी जो डीआईसीजीसी के परिसर में तैनात हैं।

17. अन्य

- 17.1.** एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है कि वे पूरी तरह से भरी गई अनुसूची/प्रतिक्रिया (सीजीएसटी और एसजीएसटी को छोड़कर सभी प्रकार के करें सहित) के लिए पारिश्रमिक की समेकित दर का उल्लेख करें, जिसके लिए डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित समय के भीतर डीआईसीजीसी को विधिवत सत्यापित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 17.2.** बैंक न्यूनतम स्वीकार्य उद्धृत मूल्य या न्यूनतम मूल्य से नीचे उद्धृत बोली को आगे औचित्य प्रदान किए बिना अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रति अनुसूची या प्रति साक्षात्कार लागत न्यूनतम स्वीकार्य उद्धृत मूल्य ओवरहेड लागतों पर विचार करने के साथ-साथ जांचकर्ताओं को देय न्यूनतम पारिश्रमिक और दैनिक भत्ते (पैरा 11.4) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। शहरी परिवारों के सर्वेक्षणों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य उद्धृत मूल्य 230 रुपये (केवल दो सौ तीस रुपये) हैं। जो बोलियां इन न्यूनतम सीमाओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें गैर-अनुपालन माना जा सकता है और बैंक के विवेकाधिकार पर अयोग्यता के अधीन किया जा सकता है।
- 17.3.** एजेंसी/बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य भारतीय रुपये में होगा और उन पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। उद्धृत मूल्य केवल इस सर्वेक्षण के लिए मान्य होगा। सर्वेक्षण कार्य के संतोषजनक समापन के अध्यक्षीन इस सर्वेक्षण के अंतिम डेटा को प्रस्तुत करने तक चयनित एजेंसी के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

- 17.4.** डीआईसीजीसी किसी भी बोली को स्वीकार नहीं करने या किसी विशेष बोली को अपने विवेकाधिकार पर स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 17.5.** यह एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी लागत और जिम्मेदारियों पर, उपकरण और उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), यदि कोई हो, की व्यवस्था करे, जो सीएपीआई आधारित सर्वेक्षण के लिए बेंचमार्क, प्रदर्शन, तकनीकी विनिर्देशों, आदि, यदि कोई हो, के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकता है।
- 17.6.** अनुबंध के नियमों और शर्तों के प्रदर्शन की निरंतरता की समीक्षा अनुबंध के पक्षकारों द्वारा की जाएगी यदि अपरिहार्य घटना दस (10) दिनों से अधिक समय तक जारी रहती है।
- 17.7.** यदि अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो यह सर्वेक्षण के लिए अनुबंध के अन्य नियमों और शर्तों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा, यदि शेष भाग अनुबंध के पक्षों के मूल इरादे को बताता है। इस तरह के अमान्य खंड को अनुबंध से अलग माना जाएगा और पार्टियां अधिकतम संभव सीमा तक, उसके निकटतम वाणिज्यिक अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करेंगी।
- 17.8.** एजेंसी सीएपीआई आधारित सर्वेक्षण के संबंध में नई प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर और प्रणाली सॉफ्टवेयर) के बारे में डीआईसीजीसी को लगातार और अचूक रूप से सलाह देने का वचन देगी।
- 17.9.** एजेंसी प्रमाणित करेगी कि उपयोग किया जाने वाला सीएपीआई उत्पाद (हार्डवेयर और प्रणाली सॉफ्टवेयर) किसी अन्य इकाई के किसी भी पेटेंट, कॉपी राइट, व्यापार रहस्य का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करता है। एजेंसी इस वारंटी के किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मांग, कार्रवाई या कार्यवाही से डीआईसीजीसी को क्षतिपूर्ति करेगी और क्षतिपूर्ति करेगी।
- 17.10.** अनुबंध को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा और अधिकार क्षेत्र केवल मुंबई की अदालतों तक ही सीमित होगा, भले ही कार्रवाई का कारण कुछ भी हो।
- 17.11.** अनुबंध को पूरा करने, समाप्ति या समाप्ति इस अनुबंध के तहत अपने जीवित संविदात्मक दायित्वों के किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी, गोपनीयता, शीर्षक और स्वामित्व से संबंधित।
- 17.12.** एजेंसी इस सर्वेक्षण के लिए लगे अपने क्षेत्र के जांचकर्ताओं, पर्यवेक्षकों आदि के लिए किसी भी दायित्व/बीमा कवर का ध्यान रखेगी, जो किसी भी कानून के तहत आवश्यक है। इस सर्वेक्षण

के लिए काम करते समय उनके जीवन या संपत्ति को किसी भी नुकसान/क्षति के मामले में डीआईसीजीसी किसी भी जांचकर्ता/उनके कानूनी उत्तराधिकारी आदि के किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे किसी भी अन्वेषक और डीआईसीजीसी के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध मौजूद नहीं होगा। एजेंसी अपने कर्मचारियों के संबंध में श्रम संबंधी कानूनों का पालन करेगी और उनका पालन करेगी, यदि लागू हो। एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों/कर्मियों के लिए अपने द्वारा लिए गए किसी भी कानून के तहत लिए जाने वाले दायित्व/बीमा कवर का प्रमाण प्रस्तुत करेगी, जब भी उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

17.13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर दिए गए खंड केवल इस बात का संकेत हैं कि अनुबंध का एक हिस्सा क्या होगा। अनुबंध और इस बोली को एक दूसरे के साथ संयोजन में पढ़ा जाएगा। यदि अनुबंध या इस दस्तावेज़ में किसी भी शब्द या खंड की व्याख्या के संबंध में पार्टियों के बीच कोई असहमति है, तो पार्टियां सहमत हैं कि डीआईसीजीसी की व्याख्या प्रबल होगी और एजेंसी पर बाध्यकारी होगी।

17.14. एजेंसी बिना किसी असफलता के नैतिकता के उच्चतम मानक को बनाए रखेगी और उसका पालन करेगी और अनुबंध के तहत काम करते समय किसी भी निषिद्ध अभ्यास का सहारा नहीं लेगी।

17.15. इस बोली के उद्देश्य के लिए डीआईसीजीसी और एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। एजेंसी द्वारा तैनात सभी श्रमिकों या कर्मियों को एजेंसी के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा और ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में डीआईसीजीसी का कोई दायित्व नहीं होगा। एजेंसी अपने द्वारा लगाए गए जनशक्ति के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होगी।

17.16. एजेंसी लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार, इस बोली के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले समझौते पर लागू स्टॉप शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगी।

17.17. परिवारों और उद्यमों पर सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसियों के पैनल के लिए बोली आमंत्रित करने वाले बोली दस्तावेज नोटिस का भी संदर्भ आमंत्रित किया जाता है (ई-बोली संख्या: आरबीआई/डीएसआईएम-केंद्रीय कार्यालय विभाग/अन्य/6/24-25/ईटी/903) उसमें विनिर्दिष्ट अन्य लागू निबंधन और शर्तों के लिए। बोलीदाताओं को उक्त ई-बोली में दी गई जानकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो इस बोली दस्तावेज का हिस्सा होगा।

This Page has been left blank intentionally.

**Notice Inviting
Financial Bid for conducting
Public Awareness Survey (PAS)
(Only through e-procurement)**



**Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Reserve Bank of India, 2nd Floor,
Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008**

This document is the property of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC). It may not be copied, distributed, or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the DICGC's written permission thereof, except for the purpose of responding to DICGC for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel/agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under Indian Laws.

Disclaimer & Disclosures:

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC), Mumbai, has prepared this document to give background information on the 'Survey Project' to the interested parties. While DICGC has taken due care in the preparation of the information contained herein and believe it to be accurate, neither DICGC nor any of its respective officers, employees, agents or advisors give any warranty or make any representations, express or implied as to the completeness or accuracy of the information contained in this document or any information which may be provided in association with it.

DICGC, Mumbai, has prepared this notice inviting tender for financial quotations from the empaneled survey agencies, selected in response to tender for Empanelment of Survey Agencies for conducting Surveys on Households and Enterprises (RBI/DSIM-Central Office Departments/Others/6/24-25/ET/903 [Empanelment of Survey Agencies]) dated August 25, 2025, for conducting various survey for the period from April 2025 to March 2028. Financial Quotation is invited from the empaneled survey agencies for conducting 'Public Awareness Survey'. Please refer to RBI website https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx?Id=23292 for list of empaneled survey agencies. The empaneled agencies are requested to submit their financial bid through M/s. MSTC website.

The information is not intended to be exhaustive. Interested parties are required to make their own inquiries and respondents will be required to confirm in writing that they have done so and they do not rely only on the information provided by DICGC in submitting the bid. The information is provided on the basis that it is non-binding on DICGC or any of its respective officers, employees, agents or advisors.

DICGC reserves the right not to proceed with the Tender or to modify the terms and conditions of the Tender at any stage. It also reserves the right to revise the timeline specified in this document or amend the tendering process or procedure as deemed necessary. Furthermore, the Reserve Bank may decline to engage in further discussions with any party submitting an expression of interest. No reimbursement of costs, of any type, incurred by parties in relation to this tender will be provided.

The proposal in response to the NIT should be signed and submitted by a person duly authorized to bind the bidding company to the details submitted in the proposal in response to the NIT. The signatory should give a declaration and through authenticated documentary evidence establish that he/she is empowered by the competent authority to sign the necessary documents and bind by the bidding. All pages of the NIT documents are to be signed by the authorized signatory. Any clarification to be sought may be sent through email at dicgcimdac@rbi.org.in.

Note: This notice is being published for information only and is not an open invitation to quote in this limited tender. Participation in this tender is by invitation only and is limited to the selected Procuring Entity's enlisted contractors. Unsolicited offers are liable to be ignored.

SCHEDULE FOR SUBMISSION OF FINANCIAL BID

E-Tender Number	DICGC/Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation /IMDAC////[Survey]
Mode of tender	e-Procurement system https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi
Date of uploading financial bid document on MSTC website	May 22, 2026
E-tender view date at MSTC website	May 22, 2026
Date of starting of financial bid	May 22, 2026, 05:00 PM
Last date for submitting financial bid	June 12, 2026, 06:00 PM
Estimated cost of the survey	₹ 17,75,500/-
Earnest Money Deposit	₹ 35,510/- The bidders will have to upload scanned copies of EMDs or proof of NEFT in MSTC e-Procurement Portal (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/) along with other supportive documents. The original copy of the bank guarantee or proof of NEFT should reach at the address of the communication before opening of the bids.
Address for sending EMD (indicating name of the RFQ on the envelop)	The Chief General Manager Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Reserve Bank of India, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai – 400 008
Transaction Fee	NIL
Date, time and venue of opening of e-tender	June 15, 2026, 03:00 PM (in person only) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Reserve Bank of India, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai – 400 008
Contact person for queries, if any:	
DICGC:	
3. Shri Bhaskar Shivshankar Birajdar, Director, Mobile: 7021740368, E-mail: bsbirajdar@rbi.org.in	
4. Shri Deepak Kumar Jena, Asst. Manager, Mobile: 9777337734, E-mail: deepakjena@rbi.org.in	
M/s MSTC Ltd:	
Centralized helpdesk for vendors: 07969066600 Email ID: helpdeskho@mstcindia.in (Please mention "HO Helpdesk" as subject while sending emails) Helpdesk at MSTC Mumbai for vendors: 7651915418/ 022 6985 6817/ 022 6985 6800 (Availability: 9:30 AM to 5:00 PM on all working days for all Technical issues (e-Tenders, System settings etc.))	

2. Public Awareness Survey (PAS)

- 1.1. The functions of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961' (DICGC Act) and 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961' framed by the Reserve Bank of India (RBI) in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the DICGC Act. The preamble of the DICGC Act states that it is an Act to provide for the establishment of a Corporation for the purpose of insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities and for other matters connected therewith or incidental thereto. The authorized capital of the DICGC is ₹ 50 crore, which is fully issued and subscribed by the RBI. The management of the DICGC vests with its Board of Directors, of which a Deputy Governor of the RBI is the Chairman.
- 1.2. DICGC proposes to launch the Public Awareness Survey (PAS) with the objective to assess and understand the level of awareness among the public regarding its functioning, role and responsibilities in safeguarding the interests of depositors and promoting financial stability. The survey aims to collect data on the public's understanding of deposit insurance, their knowledge about DICGC's initiatives and schemes, and their overall perception of DICGC's visibility, transparency, and effectiveness. Additionally, the survey can help identify areas where public awareness needs improvement and assist DICGC in developing targeted communication strategies and educational campaigns to enhance understanding and trust among the stakeholders.
- 1.3. The survey is proposed to be conducted across 15 states (19 Cities) and 3 Union Territories (3 Cities) covering 6,700 individuals. The survey will use two stage sampling methodology with polling booths/villages as first stage units (FSUs) and households as second stage units (SSUs). While FSUs are selected using circular systematic sampling, SSUs are selected using right hand rule by skipping ten households. The survey questionnaire is given in Annex A.
- 1.4. **The Agency should have its offices located in the target states given in Annex B. Proof of same should reach at the address of the communication before opening of the bids. The Bid shall be rendered invalid in case of non-submission of the said proof.**

2. Scope of Work

The scope of the outsourcing work to be provided by the Agency to DICGC is described as under:

- 2.1. **Survey Frequency:** The survey will be a one-time exercise.

- 2.2. Survey Coverage:** The survey will be conducted in 15 states (19 Cities) and 3 Union Territories mentioned in Annex B. The sampling design advised by DICGC must be adhered. DICGC, at its discretion, may increase or decrease the geographical coverage without giving any reason, whatsoever.
- 2.3. Sample Size:** The survey should cover 6,700 individuals in total from urban, semi-urban and rural households. The city-wise sample size provided by DICGC should be adhered to. The present city-wise sample size is given in Annex B. DICGC, at its discretion, may increase or decrease the sample size without giving any reason, whatsoever.
- 2.4. Type of Respondents:** Any person of the sampled household of age 18 years or above, who is either earning member or knows about the household expenses and has idea about banking.
- 2.5. Data Collection Method:** The agency has to obtain the requisite information in the format supplied by DICGC through personal interview using CAPI (Computer Assisted Personal Interview) method from the selected households in each city. In case of sudden unforeseen disruptions, the agencies must have the capability to conduct the surveys, at a very short notice, through telephonic mode (using Computer Assisted Telephonic Interview (CATI) system) or online mode, as may be deemed fit at that time as decided by the RBI.
- 2.6. Survey Questionnaire:** The survey will assess the public's understanding of deposit insurance in India, working of the DICGC and claim settlement procedure in case of liquidated banks and banks placed under All Inclusive Directions of the Reserve Bank of India. The survey questionnaire is given in Annex A.
- 2.7. Time Schedule:** DICGC shall provide time schedule for the survey and the Agency shall be required to complete the survey work as per the time schedule. Normally, the survey field work is to be completed within 10 days including Saturdays, Sundays and public holidays.
- 2.8.** The Agency shall be required to undertake the fieldwork, field supervision and ensuring authenticity of interviews, quality checks, data scrutiny, coding, data entry, and data validation of the survey as required by the DICGC. Apart from these, the Agency shall be required to provide:
- 2.8.1 Complete and clear audio recording of all the interviews. The Agency shall ensure that the quality of audio-recording is of good standard. The data and audio recordings/files must be made available (online) to DICGC on daily basis for monitoring purpose. The interviews conducted on a particular day should be uploaded and made available to DICGC on the same day.

2.8.2 GPS coordinates for the location of the interview should be captured. The coordinates must be placed with a hyperlink, which redirects the user to a web page showing the coordinate location on a map, preferably on Google maps. Responses with inaccurate location will be rejected.

2.9. DICGC reserves the sole right to change the coverage (state, district, and survey locations such as cities, towns and villages) or sample size, sampling design, survey questionnaire, etc., as and when required.

3. Materials provided by DICGC to the Agency

DICGC shall make available the following materials required for the conduct of the survey before the launch of the survey.

3.1. Survey coverage, Sample size and Sampling design.

3.2. Script of the Survey Questionnaire for CAPI.

3.3. A letter authorizing the Agency to collect the requisite information (data) from the respondents on behalf of DICGC (Agencies should not issue any letter without the prior approval of DICGC). The agency will be required to arrange printing of the authority letters etc., using the 'Master copies' provided by DICGC.

3.4. Data submission format / structure in MS-Excel format.

3.5. Guidelines for field work and filling-up the Survey Questionnaire.

3.6. Any other material as and when decided and mutually agreed by both the parties, i.e., DICGC and the Agency.

4. Duties of the Agency

4.1. The Agency i.e., successful bidder shall execute a contract with DICGC at Mumbai within 05 days of award of the project.

With reference to Field Work

4.2. The Agency shall be required to arrange sufficient hardware and software as well as qualified investigators to complete the survey on time. The Computer Assisted Personal Interview ('CAPI') instrument (hardware) in sufficient numbers with relevant software required to be used for survey work have to be arranged / procured by the Agency for both investigators training as well as for the field

work. DICGC will not bear any responsibility in this regard and no separate payment will be made by DICGC for the same.

- 4.3. The Agency shall be required to collect the information as specified in the questionnaire by interviewing households in each specified district. The Agency shall be required to develop schedule/ questionnaire for CAPI system, translate the same in regional languages, as prescribed by DICGC and send the same for vetting by DICGC.
- 4.4. The **minimum education qualification** (may be verified with the original document) for the investigators undertaking field work is **graduation**, preferably with Economics/ Statistics/ Mathematics as a subject. For field supervisor/ coordinator, the minimum qualification should be graduation and they should also have sufficient practical experience/ knowledge in the same field. Moreover, **the investigators along with their supervisor are required to attend the briefing/ training given by DICGC, without any cost to DICGC at DICGC office in Mumbai, before the commencement of the survey fieldwork.**
- 4.5. The Agency shall be required to bring sufficient number of investigators with appropriate educational qualification and other skills for the training by DICGC. This would help DICGC to identify suitable and quality investigators for the survey. **DICGC reserves the right to reject any supervisor/investigator, if found not suitable.**
- 4.6. The Agency should ensure that only those investigators who attended the training program imparted by DICGC for the specific round undertake the field work. The investigators who are deployed for the survey on a particular day are not permitted to undertake any other survey work or any other remunerative work simultaneously.
- 4.7. DICGC shall provide one round of training to the investigators at free of cost. Any additional training to the investigators by DICGC is chargeable (See Para 7.2.3).
- 4.8. The Agency must deploy minimum prescribed number of investigators for each centre/city as given in Annex B. In case of any change, the minimum number of investigators will be intimated to the Agency by DICGC. However, if needed, agency should be in a position to increase the number of investigators to complete the survey on time.

- 4.9. The Agency should strictly follow maximum number of calls / interviews allowed per investigator per round for each centre. Any calls/ interviews above the prescribed limit may be rejected.
- 4.10. The fieldwork should be conducted under proper supervision of the agency ensuring desired quality within stipulated time as per the guidelines provided by DICGC, time to time.
- 4.11. The Agency should perform thorough/ exhaustive quality checks (i.e., correctness, consistency, data entry, coding, etc.) to ensure data quality before submitting to DICGC. The Agency should ensure that there is no compromise on the data quality and any lapses will be viewed seriously (See Sub heading 7 – Performance of the Agency and Damages, if any).
- 4.12. After scrutinizing the city-wise data, the agency shall submit the entire city-wise survey data to DICGC including non-response information of each city. DICGC reserves the right to cross-check the quality and accuracy of data in the filled-in schedules through field verification (at least 5%) as well as through onsite/ telephonic verification (at least 5%). At the time of field verification, the agency should ensure that the concerned investigator conducted the survey should accompany DICGC officials for identification of the respondent. The Agency shall be penalised, if the investigator does not accompany DICGC officials during the field verification (Para 7.2.4). Also, DICGC reserves the right to reject all the interviews done by those investigators.
- 4.13. In case of any discrepancies found in the data, the partial/ whole lot pertaining to concerned investigator shall be rejected. Further, DICGC reserves the right to impose penalty in such cases (See Sub heading 7 – Performance of the Agency and penalty, if any). In the extreme scenarios **like fake calls, poor data quality, etc., DICGC reserves right to terminate the contract.**
- 4.14. **Termination of interviews may occur if respondents fail to provide requisite information in response to question number 3 and 4 of the questionnaire (see Annex). Such discontinued interviews shall be deemed as partial interviews. A successful interview is defined as the comprehensive completion of all questions of the questionnaire, ensuring the provision of all necessary information with quality**

assurance. The targeted sample size for this survey is 6,700. The agency is obligated to achieve a minimum of 6,200 successful interviews, for which they will receive the full contracted amount per interview. Compensation for partial interviews will be at a reduced rate i.e.,30% of the quoted amount per successful interview. The aggregate number of partial interviews, eligible for payment at the reduced rate, shall not exceed 500.

With reference to Data Submission

4.15. After the completion of the survey, the Agency shall be required to submit the data in soft copy to DICGC as per the prescribed format and file type, on or before the date given at the time of launching each round of survey. Also, following outputs shall be required to be submitted by the Agency to DICGC.

4.15.1 Daily Supervisory Report: The Agency should provide the specified tables (Annex- C), along with detailed data and audio recordings, to DICGC on a daily basis through a dashboard designed by the Agency for the said purpose to facilitate monitoring of the survey.

4.15.2 Daily Data: The Agency should also submit the data in prescribed electronic format, along with the audio recordings/files, on near to real time basis.

4.15.3 Formatted and Complete Database: The Agency should submit the final data along with complete audio file to DICGC in prescribed format (Annex D provided by DICGC) after due data quality checks, in stipulated time, indicated during each round of survey. The number of responses in the final data must be within the targeted sample size for each polling booth as well as for each survey centre, and any extra calls canvased by the agency must be submitted separately. It will be the sole discretion of DICGC either to accept or reject those extra calls.

4.15.4 Locational Information: The Agency should provide information regarding date-wise area allocation for each investigator to DICGC at least a day in advance to enable DICGC to monitor and conduct on-spot verification at any point in time. The Agency must ensure that the GPS coordinates of the location where the interviews are conducted are

captured accurately. Failure to capture the GPS coordinates will be seriously viewed and DICGC reserves right to cancel those interviews. Repeated occurrences of missing GPS coordinates data may attract penalty and would be considered as the violation of the contract.

4.15.5 Quality Checks: The Agency should ensure that there is no compromise of the data quality submitted to DICGC. Details of quality checks carried out by the Agency along with interview wise observations, have to be submitted to DICGC through on-line platform on a daily basis, including the list of interviews rejected through this process, with reasons thereof. The agency must ensure the consistency of the responses within the interview, as per the consistency checks provided by DICGC.

4.15.6 Audio records: The Agency should instruct the investigators to undertake proper audio recording of interviews and ensure the quality of recording. Further, the Agency should ensure that clearly audible audio-records of all interviews are made available on a daily basis to DICGC for verification.

4.15.7 Non-Response: Details of non-responding households must be submitted with reasons, if requested.

5. Time Schedule of the Survey

5.1. The survey will be conducted as a one-time exercise, commencing one to two months from execution of contract.

5.2. The Agency should strictly follow the time frame communicated by DICGC and complete the work within the specified time period. The tentative time schedule is as under:

Activities	Time schedule
Pre-Launch information to the Agency	At least five days before the launch
Investigator's Training	One or two days before start of survey field work

Launching and survey field work	<p>Normally 10 days will be given for survey fieldwork which include Saturdays, Sundays and public holidays.</p> <p>A period of 4 days (buffer period) may be given to the Agency to re-conduct the fieldwork in case of mass rejection due to poor quality of data, after the final data submission. This will be at the discretion of DICGC and attract damages (See Para 7.2.7).</p> <p>Actual dates of the survey period will be communicated through e-mail and/ or launching letters.</p>
Final Data Submission by the Agency to DICGC	Within 2 days from the close of survey field work, which include Saturdays, Sundays and public holidays.
Field Verification (for an investigator)	Any day at the discretion of DICGC after the submission of final data with one-day prior intimation to the Agency by DICGC.

5.3. Time schedule for those centres with smaller sample size will be given at the time of launching the survey.

6. Earnest Money Deposit

6.1. **The Agency is required to deposit an amount of ₹ 35,510 as Earnest Money Deposit (EMD).** The bidders will have to upload scanned copy of EMD through Bank Guarantee('BG')/ NEFT (in favour of Reserve Bank of India, Mumbai in the A/c No. 8705688 & IFSC – DICG0000002 (the 5th to 10th characters are zero) in MSTC e-Procurement Portal for DICGC (<https://www.mstcecommerce.com/eprochome/>) along with other supportive documents. The validity of the EMD (preferably in the form of Bank Guarantee) will be **six months** from the date of issue. The original hardcopy of the EMD should reach at the address of the communication before opening of the bids. A tender which is not accompanied by such EMD will not be considered for further processing. No interest shall be paid on EMD. EMD will be refunded /returned by DICGC to the agency after the completion of the financial bid process. The amount of EMD would be forfeited in the following scenarios:

- i. In case the bidder withdraws the bid prior to validity period of the bid without providing any satisfactory reason;
- ii. In case the successful bidder fails to accept and sign the contract as specified in this document without any satisfactory reason;
- iii. In case the selected bidder fails to provide the performance bank guarantee within 30 working days from the date of signing of the agreement without any satisfactory reason.

6.2. This EMD will be returned back to the unsuccessful bidder(s) without any interest after the bidding process is over. For the successful bidder (selected agency), EMD will be returned only on submission of performance bank guarantee (PBG) as may be stipulated in the contract.

7. Performance of the Agency and penalty, if any

7.1. The Agency is required to submit performance bank guarantee (PBG), as per the pro-forma (Annex F), for an amount of minimum 05 per cent of the total quoted value of annual contract, with validity upto 6 months after the completion of the contract to the satisfaction of DICGC". In the alternative, DICGC may amend the phrase 'whichever is earlier' to 'whichever is later'. In case of renewal of the contract for further period, the Agency will be required to submit fresh bank guarantee.

7.2. Time shall be considered as essence of the contract and the Agency shall be required to abide by the timelines of the survey. Any delay on part of the Agency, in the performance/execution of obligations arising out of the contract, would enable DICGC to take the following actions:

7.2.1 The agency must make all efforts to complete the survey field work in the stipulated time, conveyed at the time of launching of the survey. However, if the targeted sample size for one or more city/ cities is/are not achieved, as per the time schedule, then the Agency, with due permission from DICGC, can continue the survey field work to achieve the sample size and submit the final data (no partial data submission allowed) by end of the day ('EoD') of the following day from the close of survey fieldwork. In that case, a penalty of ₹ 20,000/- (Rupees twenty thousand only) per day shall be imposed on the Agency for the extended

period. However, under no circumstances, extension of more than 2 days shall be permitted.

- 7.2.2 In case of delay of more than 10 days in submitting the final data (no partial data submission allowed), the Agency shall be required to pay a penalty of ₹ 20,000/- (Rupees twenty thousand only) per day for each day of delay, solely attributable to the Agency.
- 7.2.3 For additional training to the investigators by DICGC, an amount of ₹ 7,000/- will be charged to the Agency per training per centre.
- 7.2.4 In case of investigators failing to accompany DICGC officials for the field verification, an amount of ₹ 5000/- per investigator will be imposed on the Agency. This will be in addition to the rejection of the interviews done by such investigator.
- 7.2.5 In case of any inconsistency in the data, the partial/ whole lot may be rejected. If such inconsistencies are observed/ repeated in the interviews conducted by a particular investigator, he/ she would be debarred from canvassing of the survey. Repetitive occurrence of such inconsistencies may result in termination of the contract.
- 7.2.6 The Agency should achieve minimum 85% sample size city-wise and minimum 90% sample size in the overall, after applying the quality check for full payment per schedule. Otherwise, the Agency would be paid at the reduced rate, i.e., 90% of quoted amount per schedule. In this case, the decision of DICGC shall be final.
- 7.2.7 For the calls / interviews done during the buffer period, the Agency shall be paid at a reduced rate i.e., 85% of the amount per schedule.
- 7.2.8 In case of fake interviews, whole or part of the work done by the investigator concerned would be rejected and such investigator will not be allowed to engage with any future round of the survey and such actions may, at the discretion of DICGC, result in termination of the contract.

7.2.9 In case the selected agency fails to undertake the work, or to meet DICGC's requirements in terms of quality and timelines, DICGC shall be at liberty to award the work to another empanelled agency, at the risk and cost of the failed agency. In addition to terminating the contract, DICGC may also decide to debar/ delist the agency concerned from the panel as well as from undertaking any projects of the DICGC, in the present as well as in future. Further, DICGC, without prejudice to its other remedies under this document, deduct from the purchase order value, as liquidated damages, a sum equivalent to 0.5 percent of the total consideration amount for each and every calendar day of delay, subject to a maximum limit of 10 percent of the Total Purchase Order Value. Such penalty will be deducted from the bills of the Bidder OR from the invocation of the Bank Guarantee. The decision of DICGC will be final and binding on all concerned.

8 Ownership of Document and Data

The Agency shall agree that the ownership, copyright and other intellectual property rights in respect of all documents and data generated, collected or produced during the course of the survey shall be the exclusive property of DICGC and the Agency shall have no claim or title, whatsoever, over such documents or data.

9 Confidentiality of Information

9.1. The Agency agrees to adhere to the obligations set forth in this clause and to comply with the applicable data protection laws, ensuring the utmost confidentiality and protection of Personal Data.

9.1.1 **Obligation of Confidentiality:** The Survey Agency acknowledges and agrees that, in the course of performing its obligations for the survey as may be stipulated under the contract to be executed with the successful agency, it may collect, access, or process personal confidential information ("Personal Data") pertaining to individuals. The Agency shall treat all such information as strictly confidential and shall comply with the provisions of the applicable data protection laws [including Digital

Personal Data Protection Act, 2023 ("DPDP Act"), and DPDP Rules, 2025 (as and when brought into effect)] and any applicable rules, regulations, or guidelines issued or to be issued thereunder.

- 9.1.2 **Collection and Use:** The Agency shall collect Personal Data solely for the purposes which are explicitly authorized for survey by DICGC and shall ensure that such collection is lawful, fair, and transparent. The Agency shall process Personal Data only to the extent necessary for fulfilling its contractual obligations and shall not use the data for any unauthorized purposes.
- 9.1.3 **Protection and Safeguarding:** The Agency shall implement and maintain appropriate technical, organizational, and security measures to protect Personal Data against unauthorized access, disclosure, alteration, destruction, or loss. These measures shall be in compliance with the applicable data protection laws and shall be subject to periodic review.
- 9.1.4 **Disclosure of Personal Data:** The Agency shall not disclose or share Personal Data with any third party without the prior written consent of DICGC, except where required by law or in compliance with orders passed by judicial/ statutory / government authorities.
- 9.1.5 **Access Control:** Access to Personal Data shall be restricted to authorized personnel of the Agency who require such access to perform their duties under this agreement. All such personnel shall be bound by strict confidentiality obligations and trained in compliance with the applicable data protection laws.
- 9.1.6 **Retention and Disposal:** The Agency shall retain Personal Data only for as long as the same is necessary to fulfil the purposes for which it was collected or as required under applicable law. Upon completion of the project or termination of this agreement, the Agency shall securely destroy or return all Personal Data, as instructed by DICGC, ensuring that no residual copies remain.
- 9.1.7 **Breach Notification:** In the event of any actual or suspected data breach involving Personal Data, the Agency shall immediately notify DICGC and the Data Protection Board of India (as and when set up under DPDP Act)

and cooperate fully in mitigating the impact of the breach, investigating its cause, and implementing corrective actions as required.

9.1.8 Indemnity: The Agency shall indemnify and hold harmless DICGC against any claims, damages, or penalties arising out of the Agency's breach of this confidentiality clause or its non-compliance with the applicable data protection laws.

9.1.9 Audit and Monitoring: DICGC reserves the right to audit the Agency's data protection practices and compliance with this clause at any time during the term of the contract.

9.1.10 Survival: The obligations under this confidentiality clause shall survive the expiration or termination of the contract.

10 Undertaking by the Agency

10.1 The Agency shall not subcontract the survey fieldwork to any organization, person, firm or its franchisee without the prior written approval of DICGC; It shall not permit anyone other than the Agency's personnel to perform any work required to be done by the Agency for DICGC without the prior written consent of DICGC.

10.2 The appointment of any sub-contractor, if any, with the permission of DICGC shall not absolve the Agency of its responsibilities and the Agency shall remain solely responsible to DICGC for the performance and completion of all the obligations under the contract.

10.3 In the event that the Agency ceases to conduct business in the normal course or winds up or avails itself of or becomes subject to any proceeding under any Act or statute of any country or state relating to insolvency, the contract with the Agency shall forthwith, stand terminated and be of no further force or effect and any property or rights of either party, tangible or intangible, shall forthwith be returned to it.

10.4 The Agency is expected to reply promptly to all queries/ complaints that may be raised by DICGC from time to time. Evasive attitude by the Agency would be treated as "Unsatisfactory performance" and this will be taken into consideration by DICGC at the time of renewal of the contract.

- 10.5** Any publicity by the Agency in which the name of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is to be used should be done only with the explicit written permission of DICGC.
- 10.6** The Agency shall adhere to all applicable laws of the land and also the 'rules, regulations and guidelines' prescribed by various regulatory, statutory and Government authorities including but not limited to Minimum Wages Act, other labour laws and applicable data protection laws. The Agency shall indemnify DICGC from any claim or demand, action or proceeding, directly or indirectly resulting from or arising out of any breach or alleged breach of any statute, rules, regulations or guidelines, and the contract as well.
- 10.7** The Agency undertakes that in fulfilling the obligations, the Agency shall abide by all applicable laws, codes, rules, directions and notifications, etc., in force in India. DICGC shall not be held liable and responsible for breach or violation of any law by the Agency, either directly or indirectly.

11 Payment Terms

- 11.1** No advance payment will be made to the Agency for the survey fieldwork. All payments will be made only after the completion of the survey fieldwork subject to complete satisfaction of DICGC following the above terms and conditions.
- 11.2** The payment would be made according to the number of responses accepted by DICGC. The quality checks include removing fake calls (e.g., interviews done by a person in the name of a trained investigator, interviews not actually done etc.), calls more than the specified no. of calls per polling booth, calls more than the specified no. of calls per day per investigator, calls of untrained investigators, etc. The Agency should achieve minimum 85% sample size city-wise and minimum 90% sample size in the overall, after applying the quality check for full payment per schedule. Otherwise, the Agency would be paid at the reduced rate, i.e., 90% of quoted amount per schedule. In this case, the decision of DICGC shall be final.
- 11.3** If the number of accepted schedules is below 85% for any city, then DICGC shall seek explanation from the Agency and reserves right to terminate the contract with the selected agency and award the project to another agency in case of repetitive occurrence.

- 11.4 Remuneration to be paid to Investigators by the Agency:** The agency must pay a minimum remuneration to the investigators. A minimum amount of Rs.175/- per schedule/ interview and a minimum daily allowance (including travel expenses) of Rs.290/- per day must be paid to an investigator, irrespective of any penalty imposed by DICGC on the Agency. This will be in addition to the obligation of the agency under Para 10.6 of this document i.e., the Agency shall adhere to all applicable laws of land and 'rules, regulations and guidelines' prescribed by various regulatory, statutory and Government authorities e.g., Minimum Wages Act and other labour laws.
- 11.5** No remuneration shall be paid in respect of the following survey responses:
- i. for which filled-in CAPI data is not submitted because either the households are not available or refuse to respond for any other reasons.
 - ii. which is incomplete or not filled-in accordance with the instructions/ guidelines, provided by DICGC
 - iii. where data in soft form is not found in accordance with the instructions/ guidelines provided by DICGC.
 - iv. if the complete filled-in survey questionnaires are found to be fake after verification by DICGC.
- 11.6** Though the remuneration will not be paid in regard to incomplete schedules submitted to DICGC, the Agency is required to submit a status-report about those non-responses. This is for the purpose of collecting information on non-responses. No charges/fees will be paid for this report.
- 11.7** Any other expenses, on whatever account, incurred by the Agency for field work and data tabulation job as envisaged under the contract, including the salary, wages, allowances, payment for accommodation, transportation etc., of the resource persons employed or engaged by the Agency for the completion of the outsourcing work at any place, taxes to the Government, etc., arising out of the contract, shall be fully paid/met/borne by the Agency only.
- 11.8** In pursuance of the provisions of Section 194C of Income Tax Act, it is obligatory upon DICGC to deduct tax at the applicable rate on the amount payable under the contract to any person providing service to DICGC. If the

applicable tax is not payable by the Agency, a certificate of exemption from the concerned Income Tax Officer may be produced by the Agency. DICGC shall also deduct any other taxes from the bill as may be applicable at the time of making payment.

11.9 DICGC will not bear any tax (except CGST and SGST) and will neither be responsible for payment of any tax nor will be subject to TDS.

11.10 All payments will be made by DICGC only at Mumbai, in Indian Rupees, to an account designated by the Agency. Any change in the account number for the purpose of the payment arising out of the contract shall be communicated by the Agency to DICGC, in writing, forthwith.

12 Governing Language

The contract that is executed with the successful bidder shall be originally drawn up in the English language and signed and executed in bilingual form (by way of translation in Hindi) to comply with the provisions of section 3(3) of the Official Languages Act, 1963. In the event of any conflict between English and Hindi texts of the contract, English version shall prevail. All notices, correspondence, information, literature, data, manuals, procedures and other documents required under the contract shall be in the English language only.

13 Arbitration

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation and the Agency shall make every effort to resolve amicably, by direct negotiation and mutual discussions, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If after thirty (30) days from the commencement of such negotiations, DICGC and the Agency have been unable to resolve amicably a dispute; either party may give a written notice to the other Party clearly setting out therein the specific dispute/s and/ or difference/s, which is required to be arbitrated upon. Such dispute/s and/ or difference shall be referred to a sole arbitrator mutually agreed upon. Any such arbitration would be governed by the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996. All legal suits, actions, proceedings, disputes and differences of any kind arising in this connection shall be subject to jurisdiction of courts at Mumbai only. The venue and seat of arbitration shall be Mumbai, India.

14 Termination

- 14.1** Either Party would have right to terminate the contract by giving a written notice of one month in advance to the other Party in the matter. In the event of the contract being terminated by whichever party and for whatsoever reason, DICGC shall only be liable to make payments of the entire amount due under the contract up to the effective date of termination for which services have been rendered by the Agency, subject to the provisions of Para 4, 7, 8, 9, 10 and 11 hereinabove and the Agency shall be liable to perform all its obligations, including handing over of the material (like data collected, etc., till the date of such termination) to DICGC under the contract.
- 14.2** DICGC will examine the overall quality of the work done by the Agency through audio, telephonic, on-spot, and field verification in the survey. In case the selected agency fails to meet the expectations of DICGC in terms of the quality, timeliness and response rate of the survey data, DICGC will be at liberty to terminate the contract with the selected agency and award the project to any other agency at the risk, expense and cost of the failed agency. Also, DICGC shall not be liable to make any payments thereof.
- 14.3** In the event of the termination of the contract, wholly or partly, DICGC is free to do the CAPI based survey from alternative sources, similar to those undelivered/ unperformed by the Agency and in that event, the Agency will be liable to pay the price differentials, if any.
- 14.4** However, till the termination of the contract, if decided by DICGC, the Agency shall be bound to extend the services, on payment as per the contract.
- 14.5** Termination of the contract, either wholly or partly in respect of any survey, will not absolve the Agency of any other surviving contractual obligations.
- 14.6** At any stage, the awarding of a project or discontinuing the contract will be at the discretion of DICGC and subject to its satisfaction with regard to the criteria laid down by DICGC. The decision of DICGC in matter of award or termination of the contract will be final. No dispute shall be raised with regard to termination of the contract and the DICGC shall not be liable for any costs or damages or consequences for termination, if any.

15 Force Majeure

- 15.1** "Force Majeure" shall include an event, circumstance or situation beyond the control of the parties including an event, circumstance or situation which is a result of or caused by fires, floods, power failure, acts of God, acts of public enemy, civil commotion, sabotage, war, insurrections, riots, terrorist attacks, labour disturbances, strikes, lockouts, go-slow, damage to machinery on account of accidents or passing of any statutory order by eligible authority/ies prohibiting performance of such obligations and restrictions of any country affecting the export of Goods or technology to DICGC or import regulations or requirements of India, whatever the causes are, which would affect the conduct of the survey. However, this does not include Agency's default or negligence or carelessness or failure to assess the reasonable consequences of an act on the part of the Agency, resulting in such a situation.
- 15.2** If either party is prevented from the performance of its obligations under the contract in whole or part for reasons of Force Majeure, which is beyond the control of that party, the affected party shall notify the other party in writing of occurrence of such Force Majeure event within ten days from the date of occurrence of Force Majeure.
- 15.3** The affected party shall not be responsible for any failure to perform its obligation under the contract due to occurrence of such Force Majeure event(s), even after exertion of best efforts to prevent such occurrence.
- 15.4** Both parties will continue to perform the obligations under the contract with due diligence as far as they can be reasonably performed and will seek all reasonable alternative means for the performance and the completion of the obligations, arising out of the contract and affected by the event of Force Majeure.
- 15.5** Either party shall resume the performance and completion of all such contractual obligations, as may be affected by Force Majeure, as soon as practicable, after such event have come to an end or ceased to exist, after notifying the other party in writing thereof and subject to the instructions issued.
- 15.6** If an event of Force Majeure continues for a period of sixty (60) days or more, continuation of the performance of the contract shall be reviewed by

both the parties and DICGC reserves the right to terminate the contract in such an event.

15.7 If the contract is terminated by occurrence of force majeure event, the payment shall commensurate with the part of the contract performed.

16 Sexual Harassment

16.1 The Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of DICGC, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Agency and the Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

16.2 Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee/staff/personnel of the Agency against any employee of DICGC shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by DICGC.

16.3 The Agency shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the Agency, for instance any monetary relief to DICGC's employee, if sexual violence by the employee of the Agency is proved.

16.4 The Agency shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

16.5 The Agency shall provide a complete and updated list of its employees etc. who are deployed within DICGC's premises.

17 Others

- 17.1** The agencies are requested to quote consolidated rate of remuneration per completely filled-in schedule/response (inclusive of all type of taxes except CGST and SGST) for which duly verified data will be submitted to DICGC within the time stipulated by DICGC.
- 17.2** The Bank reserves the right to reject a bid quoted below the minimum acceptable quoted price or floor price without providing further justification. The minimum acceptable quoted price per schedule or per interview cost is determined based on the minimum remuneration and daily allowance payable to investigators (para 11.4), along with consideration of overhead costs. The minimum acceptable quoted prices for the urban household surveys are Rs. 230/- (Rupees two hundred thirty only). Bids that do not meet these minimum thresholds may be deemed non-compliant and subject to disqualification at the sole discretion of the Bank.
- 17.3** Price quoted by the agency/bidder shall be in Indian Rupees and shall be final and binding on them. The quoted price will be valid for this survey only. The contract with the selected agency will be executed till submission of final data of this survey , subject to satisfactory completion of the survey work.
- 17.4** DICGC reserves the right not to accept any bid or, to accept or reject a particular bid at its sole discretion without assigning any reason whatsoever.
- 17.5** It shall be the sole responsibility of the Agency to arrange, at its own cost and responsibilities, the tools and equipment (hardware and software), if any, which may be required for the demonstration of the benchmarks, performance, technical specifications, etc., if any, for CAPI based survey.
- 17.6** Continuation of the performance of terms and conditions of the contract shall be reviewed by the Parties to the contract if the Force Majeure continues beyond ten (10) days.

- 17.7** If any of the terms and conditions of the contract is held invalid, illegal or unenforceable, that will not affect the validity, legality or enforceability of the other terms and conditions of the contract for the survey, if the remaining part conveys the original intention of the parties to the contract. Such invalid clause shall be deemed to have been severed from the contract and the parties shall, to the maximum extent possible, try to arrive at the closest commercial meaning thereof.
- 17.8** The Agency would undertake to continuously and unfailingly advise DICGC of new technology (hardware and system software) in regard to the CAPI based survey.
- 17.9** The Agency shall certify that the CAPI product (hardware & system software) to be used does not violate or infringe upon any patent, copy right, trade secret of any other entity. Agency shall indemnify and keep DICGC indemnified from any claim or demand, action or proceeding, directly or indirectly resulting from or arising out of any breach or alleged breach of this warranty.
- 17.10** The law governing the contract shall be the Indian law and the jurisdiction shall be limited to the courts of Mumbai only, irrespective of the place of the cause of action.
- 17.11** The completion, expiry or termination of the contract will not absolve either Party of its surviving contractual obligations under this contract, relating to confidentiality, title and ownership.
- 17.12** The Agency shall take care of any liability / insurance cover to its field investigators, supervisors, etc., engaged for this survey which is required under any law. DICGC will not be responsible for any claim from any of the investigators/their legal heir etc. in case of any loss/damage to their life or property while working for this survey. No binding legal relationship will exist between any such investigator(s) and DICGC. The agency shall adhere to and comply with labour related laws in respect of its employees, if applicable. The agency shall submit the proof of liability/insurance cover required to be

taken under any law, taken by it for its employees/staff/personnel, whenever it is required to submit the same.

17.13 It is clarified that the clauses enumerated hereinabove are only indicative of what would form a part of the contract. The contract and this bid shall be read in conjunction with each other. If there is any disagreement between the parties regarding the interpretation of any term or clause in the contract or this document, the parties agree that the interpretation of DICGC shall prevail and be binding on the Agency.

17.14 The agency shall maintain and observe without fail the highest standard of ethics and shall not resort to any Prohibited Practice while carrying out the work under the contract.

17.15 There shall be no employer- employee relationship between DICGC and the persons engaged by the agency for the purpose of this tender. All the workers or personnels deployed by the agency shall be considered as employees of the agency and DICGC shall not have any liability whatsoever with regard to such workers/employees. The agency shall be vicariously liable for the manpower engaged by it.

17.16 The agency shall be liable and responsible to pay the applicable stamp duty and other charges on the Agreement(s) to be executed in respect of this tender, as per applicable stamp laws.

17.17 A reference is also invited to the tender document notice inviting tender for Empanelment of Survey Agencies for conducting Surveys on Households and Enterprises (E-tender No.: RBI/DSIM-Central Office Departments/Others/6/24-25/ET/903) for other applicable terms and conditions specified therein. Bidders shall be guided by the information given in the said e- tender which shall form part of this tender document.



**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
PUBLIC AWARENESS SURVEY ON DEPOSIT INSURANCE 2026**

Survey Questionnaire

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India, conducts the Public Awareness Survey (PAS) to assess understanding of deposit insurance coverage, processes and related communication. Respondents' personal details are kept strictly confidential, and only aggregated findings are analysed and disseminated.

Block I: Respondent's Details

- 1) Name (Optional): _____
- 2) Contact no (Optional) _____
- 3) Category/Occupation:

(i) Financial Sector Employee	(ii) Other employees	(iii) Self-employed/ Business	(iv) Homemaker
(v) Daily worker	(vi) Retired person	(vii) Others (incl. unemployed, students etc.)	

- 4) Education Qualification of the respondent

(i) Below 10 th Std.	(ii) 10 th Std- Graduate	(iii) Post Graduate and above
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

- 5) Average monthly Household/ Family Income (optional):

(i) Less than ₹ 10 thousand	(ii) ₹ 10 thousand- ₹ 50 thousand	(iii) ₹ 50 thousand- ₹ 1 lakh	(iv) ₹ 1 lakh and above
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Block II: Basic information about Deposit Insurance:

Q.No.1 Do you have a bank account? (Yes/No)

Q.No.2 If you deposit money in a bank, do you think depositing money in bank is safe? (Yes/No/No Idea)

Q.No.3 Have you heard about Deposit Insurance? (Yes/No)

Q.No.4 Are you aware about DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)? (Yes/No)

If answer to Q.No.3 & 4 both is No, the investigator may terminate the interview and query the following:

Q.No.5 How do you think DICGC could improve public awareness about deposit insurance?

(i) TV, Radio Advertisements	(ii) Social Media	(iii) Through Famous Personalities
(iv) Banks/ Public Places	(v) Workshops, Webinars etc	(vi) Any other medium (Please specify)

If answer to Q.No.3/ 4 is Yes, then

Q.No.6 How did you first know about DICGC? (Choose all applicable answers)

(i) Through Bank	(ii) News (Electronic and Print)	(v) Others (Please specify)
(iii) Social media	(iv) Friends	

Q.No.7 Have you ever seen any advertisement or public campaign about deposit insurance? (Yes/No)

Block III: Awareness about Deposit Insurance Scheme

Q.No.1 Which types of deposits are covered/insured by DICGC? (Choose applicable answers)

(i) Only Deposits of SB A/c	(ii) Only Term (Fixed/Recurring) Deposit A/cs	(iii) Only Deposits of Current A/c	(iv) Only deposit of SB & Current A/c
(V) Only SB & Term deposits	(vi) Only Current & Term deposits	(vii) All types of deposits + interest	(viii) No Idea

Q.No.2 Would you be willing to pay an extra premium to fully insure your entire bank deposit? (Options Yes/No)

Q.No.3 What is the maximum current deposit insurance coverage? (Select one)

(i) Up to ₹1 lakh	(ii) Up to ₹5 lakh	(v) No Idea
(iii) Up to ₹10 lakh	(iv) Entire deposit amount plus interest	

Q.No.4 Do you think the current deposit insurance coverage limit is sufficient? (Yes/No/No Idea)

If No, then

Q.No.5 In your view, what should be the deposit insurance coverage limit?

(i) ₹7.5 lakh	(ii) ₹10 lakh	(v) Any other amount (Please specify)
(iii) ₹15 lakh	(iv) Entire Deposit plus interest	

Q.No.6 Of the following institutions, which are covered under Deposit Insurance Scheme?

(i) All public sector banks	(ii) Foreign bank branches in India	(iii) All cooperative banks
(iv) All private sector banks	(v) All credit cooperative societies	(vi) Non-Bank Finance Companies

Q.No.7 Of the following financial instruments, which are not covered under Deposit Insurance Scheme?

(i) Stocks and bonds	(ii) Mutual funds	(ii) Exchange Traded Funds (ETFs)
(iv) Cryptocurrencies	(v) Prepaid Payment Instruments (E.g., Paytm Wallet, GPay Wallet, etc.)	(vi) No Idea

Q.No.8 Who pays the premium for Deposit Insurance? (Choose applicable answers)

(i) Government	(ii) Depositors	(v) No Idea
(iii) Banks	(iv) RBI	

Q.No.9 Under which circumstances, depositors are eligible for the deposit insurance claim?

(i) When license of the bank gets cancelled.	(ii) When RBI puts restrictions on withdrawal from the bank (AID)
(iii) Both (i) & (ii)	(iv) No Idea

Q.No.10 If your bank fails or is placed under restrictions by RBI (i.e. AID), what should you do regarding your deposits?

(i) Contact Bank	(ii) Contact Deposit Insurer, i.e. DICGC
(iii) Contact Police	(iv) No Idea

Q.No.11 Do you have any alternate account for financial exigencies in case your bank is placed under restrictions by RBI? (Yes/ No)

Q.No.12 Do you know about deposit claim process under DICGC? (Yes/No)

If answer to Q No 12 is Yes, then

Q.No.13 In how many days your claim will be settled in case your bank is placed under restrictions by RBI (i.e., AID)?

(i) 30	(ii) 60	(v) No Idea
(iii) 90	(iv) 120	

Q.No.14 What support would you expect from DICGC regarding the deposit claim process?

(i) Reducing the claim settlement time (existing time) 90 days to 45 days in case of AID banks
(ii) Reducing the claim settlement time (existing time) 60 days to 30 days in case of liquidated banks
(iii) Active and enhanced (two-way communication Chatbot on DICGC website
(iv) IVR system in DICGC for queries
(v) Special claim settlement scheme for Senior Citizen

If answer to Q No 12 is No, then

Q.No.15 How do you think DICGC could improve public awareness about deposit insurance?

(i) TV, Radio Advertisements	(ii) Social Media	(iii) Banks/ Public Places
(iv) Workshops, Webinars etc	(v) Any other medium (Please specify)	

Table: Distribution of Respondents based on State/UT and City

Sr. No.	State/UT	City Name	No. of Respondents	Minimum No of Investigators	Maximum interviews per Investigators
1	Assam	Guwahati	300	3	100
2	Bihar	Patna	300	3	100
3	Chandigarh	Chandigarh	300	3	100
4	Chhattisgarh	Raipur	300	3	100
5	Delhi	Delhi	500	5	100
6	Gujarat	Ahmedabad	300	3	100
7	J&K	Jammu	100	1	100
8	Jharkhand	Ranchi	300	3	100
9	Karnataka	Bengaluru	500	5	100
10	Kerala	Thiruvananthapuram	300	3	100
11	Madhya Pradesh	Bhopal	300	3	100
12	Maharashtra	Mumbai	500	5	100
		Nagpur	300	3	100
13	Odisha	Bhubaneswar	300	3	100
14	Rajasthan	Jaipur	300	3	100
15	Tamil Nadu	Chennai	500	5	100
16	Telangana	Hyderabad	500	5	100
17	Uttar Pradesh	Lucknow	300	3	100
18	West Bengal	Kolkata	500	5	100
Total Respondents			6,700		

Table-1: Status of Completion of Field Work

	Jun-2026
Start of Field Work	dd-mmm-yyyy (T Day)
End of Field Work	dd-mmm-yyyy (T+9 Day)
Date of Report	dd-mmm-yyyy (T+2 Day)

City-wise Status of Field Work

Sr. No.	State/UT	City Name	Target	Achieved	Target Achieved %	Pending %
1	Assam	Guwahati	300			
2	Bihar	Patna	300			
3	Chandigarh	Chandigarh	300			
4	Chhattisgarh	Raipur	300			
5	Delhi	Delhi	500			
6	Gujarat	Ahmedabad	300			
7	J&K	Jammu	100			
8	Jharkhand	Ranchi	300			
9	Karnataka	Bengaluru	500			
10	Kerala	Thiruvananthapuram	300			
11	Madhya Pradesh	Bhopal	300			
12	Maharashtra	Mumbai	500			
		Nagpur	300			
13	Odisha	Bhubaneswar	300			
14	Rajasthan	Jaipur	300			
15	Tamil Nadu	Chennai	500			
16	Telangana	Hyderabad	500			
17	Uttar Pradesh	Lucknow	300			
18	West Bengal	Kolkata	500			

Annex D

DICGC – Data Format

Serial Number	Date of Interview	Interview Start Time	Interview End Time	Latitude of the survey location	Longitude of the survey location	State	District	Centre/ Village name
SR_NO	CANVAS_DT	S_TIME	E_TIME	LATITUDE	LONGITUDE	STATE	DISTRICT	Centre_Vill_Nm

Name of the respondent	Flat/ Survey No.	Building Name	Locality/ Area Name	Street Name	PINCODE	Landmark
NAME	FLAT_NO	BLDG_NM	AREA_NM	ST_NM	PINCODE	LANDMARK

Contact number	Gender (1=Male; 2=Female; 3=Others)	Age of the respondent (in years) (Min. 18+ years)	Age group of the respondents	Occupation of the Respondent	Educational Qualification of the respondent	Average monthly Income of the Household
PH_NO	GENDERCODE	AGE	AGEGROUP	OCC_CAT	RESP_EDUCATION	MONTHLY_INCOME

Block 2: Respondent's feedback

Have Bank Account?	Is your deposit money safe in bank A/c?	Heard about Deposit Insurance?	Aware of the nature of DICGC?
Q1	Q2	Q3	Q4

Block 2: Respondent's feedback (Continued)

If answer @Q.3 & @Q.4 = 'No', DICGC could improve awareness

TV, Radio Advertisements	Social Media	Through Famous Personalities	Banks/ Public Places	Workshops, Webinars etc	Any other medium (Please specify)
Q5_(i)	Q5_(ii)	Q5_(iii)	Q5_(iv)	Q5_(v)	Q5_(vi)

Block 2: Respondent's feedback (Continued)

If answer @Q.3/ @Q.4 = 'Yes',
How do you know about DICGC?

Through Bank	News (Electronic and Print)	Social media	Friends	Others (Please specify)
Q6_(i)	Q6_(ii)	Q6_(iii)	Q6_(iv)	Q6_(v)

Block 2: Respondent's feedback (Continued)

Have you ever seen any advertisement or public campaign about deposit insurance

Q7

Block 3: Respondent's feedback (continued...)

Types of deposits insured by DICGC

Types of deposits insured by DICGC								Would you pay an extra premium to fully insure your entire bank deposit	Coverage of Deposit insurance
Dep. Of SBs	Term Dep.	Current A/c	SB + Current	Only SB + Term Dep.	Only Current + Term Dep.	Dep. + Int.	No idea	Q2	Q3
Q1_(i)	Q1_(ii)	Q1_(iii)	Q1_(iv)	Q1_(v)	Q1_(vi)	Q1_(vii)	Q1_(viii)		

Current deposit insurance coverage limit is sufficient?

If answer @Q.4 = 'No'

What should be the deposit insurance coverage limit?

Q4	₹7.5 lakh	₹10 lakh	₹15 lakh	Entire Dep. + Int.	Any other Amt
	Q5_(i)	Q5_(ii)	Q5_(iii)	Q5_(iv)	Q5_(v)

Block 3: Respondent's feedback (continued...)

Institutions Insured by DICGC

PSBs	Foreign Bank Br in India	Co-op Banks	PvSBs	Co-op Soc.	NBFCs				
Q6_(i)	Q6_(ii)	Q6_(iii)	Q6_(iv)	Q6_(v)	Q6_(vi)				
Block 3: Respondent's feedback (continued...)									
Financial instruments not covered under DIS									
Stocks and bonds	Mutual funds	ETFs	Cryptocurrencies	Prepaid Payment Instruments	No Idea				
Q7_(i)	Q7_(ii)	Q7_(iii)	Q7_(iv)	Q7_(v)	Q7_(vi)				
Block 3: Respondent's feedback (continued...)									
Payment of Premium for Deposit Insurance									
Government	Depositors	Banks	RBI	No Idea					
Q8_(i)	Q8_(ii)	Q8_(iii)	Q8_(iv)	Q8_(v)					
Block 3: Respondent's feedback (continued...)									
Depositors eligible for the deposit insurance claim									
Bank's license cancelled	Banks under AID		Both	No Idea					
Q9_(i)	Q9_(ii)		Q9_(iii)	Q9_(iv)					
Block 3: Respondent's feedback (continued...)									
If Banks under AID, Depositor should contact									
Bank	DICGC		Police	No Idea					
Q10_(i)	Q10_(ii)		Q10_(iii)	Q10_(iv)					
Block 3: Respondent's feedback (continued...)									
If Banks under AID, does depositor has an alternate A/c for financial exigencies					Aware of the deposit claim process?				
Q11					Q12				
Block 3: Respondent's feedback (Continued)									
If answer @Q.12= 'Yes',									
Days for claim settlement if bank is under AID					Expectations from DICGC regarding claim settlement				
30	60	90	120	No Idea	Claim settlement time from 90 to 45 days in case of AID	Claim settlement time from 60 to 30 days in case of liquidation	2-way communication Chatbot on DICGC website	IVR system in DICGC for queries	Special claim settlement scheme for Senior Citizen
Q13_(i)	Q13_(ii)	Q13_(iii)	Q13_(iv)	Q13_(v)	Q14_(i)	Q14_(ii)	Q14_(iii)	Q14_(iv)	Q14_(v)
Block 3: Respondent's feedback (Continued)									
If answer @Q.12 = 'No', DICGC could improve awareness									
TV, Radio Advertisements		Social Media		Banks/ Public Places	Workshops, Webinars etc		Others (Please specify)		
Q15_(i)		Q15_(ii)		Q15_(iii)	Q15_(iv)		Q15_(v)		
Field-work Details									
Investigator Code	Investigators Name	Name of Polling Booth/ Village	Unique Identification Number of Polling Booth	Population Group (Rural/ Urban/ Semi-urban/ Metro)					
INVES_CODE	INVES_NM	PB_NAME	UID_PB	Centre_Type					

Important List of Values

Occupation	Code
Financial Sector Employee	1
Other employees	2
Self-employed/ Business	3
Homemaker	4
Daily worker	5
Retired person	6
Others (incl. unemployed, students etc.)	7
Average monthly Family Income	Code
Less than ₹ 10 thousand	1
₹ 10 thousand- ₹ 50 thousand	2
₹ 50 thousand- ₹ 1 lakh	3
₹ 1 lakh and above	4

Block 2- Q.5	Code
TV, Radio Advertisements	1
Social Media	2
Through Famous Personalities	3
Banks/ Public Places	4
Workshops, Webinars etc	5
Any other medium (Please specify)	6

Block 3- Q.1	Code
Only Deposits of SB A/c	1
Only Term (Fixed/Recurring) Deposit A/cs	2
Only Deposits of Current A/c	3
Only deposit of SB & Current A/c	4
Only SB & Term deposits	5
Only Current & Term deposits	6
All types of deposits + interest	7
No Idea	8

Block 3- Q.6	Code
All public sector banks	1
Foreign bank branches in India	2
All cooperative banks	3
All private sector banks	4
All credit cooperative societies	5
Non-Bank Finance Companies	6

Block 3- Q.7	Code
Stocks and bonds	1
Mutual funds	2
Exchange Traded Funds (ETFs)	3
Cryptocurrencies	4
Prepaid Payment Instruments (E.g., Paytm Wallet, GPay Wallet, etc.)	5
No Idea	6

Block 3- Q.10	Code
Contact Bank	1
Contact Deposit Insurer, i.e. DICGC	2
Contact Police	3
No Idea	4

Educational Qualification	Code
Below 10 th Std.	1
10 th Std- Graduate	2
Post Graduate and above	3

Choices	Code
Yes	1
No	2

Block 2- Q.6	Code
Through Bank	1
News (Electronic and Print)	2
Social media	3
Friends	4
Others (Please specify)	5

Block 3- Q.3	Code
Up to ₹1 lakh	1
Up to ₹5 lakh	2
Up to ₹10 lakh	3
Entire deposit amount plus interest	4
No Idea	5

Block 3- Q.5	Code
₹7.5 lakh	1
₹10 lakh	2
₹15 lakh	3
Any other amount	4

Block 3- Q.8	Code
Government	1
Depositors	2
Banks	3
RBI	4
No Idea	5

Block 3- Q.9	Code
When license of the bank gets cancelled.	1
When RBI puts restrictions on withdrawal from the bank (AID)	2
Both (i) & (ii)	3
No Idea	4

Block 3- Q.13	Code
30	1
60	2
90	3
120	4
No Idea	5

Block 3- Q.15	Code
TV, Radio Advertisements	1
Social Media	2
Banks/ Public Places	3
Workshops, Webinars etc	4
Any other medium	5

Block 3- Q.14	Code
Reducing the claim settlement time (existing time) 90 days to 45 days in case of AID banks	1
Reducing the claim settlement time (existing time) 60 days to 30 days in case of liquidated banks	2
Active and enhanced (two-way communication Chatbot on DICGC website	3
IVR system in DICGC for queries	4
Special claim settlement scheme for Senior Citizen	5

(On the letter head of the Agency)

The Chief General Manager
 Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
 Reserve Bank of India, 2nd Floor,
 Opp. Mumbai Central Railway Station,
 Byculla, Mumbai – 400 008

Financial Quotation: Public Awareness Survey (PAS)

With respect to RFQ dated _____ for the PAS, we submit our financial bid as follows:

Sr. No	Particulars	Rate per Interview (in Rs.) * \$\$
1	Public Awareness Survey (PAS)	

* **Rate** may be quoted for per filled-in schedule/ interview, as required by the RBI (inclusive of all applicable taxes and applicable cess/ surcharges thereon, except CGST and SGST, and will be subject to TDS). Further, the rate should, inter alia, include the following:

- i. Cost of Survey fieldwork as per schedule using CAPI.
- ii. Cost of supervision /Scrutiny /ensuring authenticity of interviews /quality checks/ coding of survey data.
- iii. Soft version of data as per the format provided by DICGC.
- iv. Cost of hardware/software used for CAPI and survey tabulations.
- v. All other relevant charges, e.g., travelling, postage, etc.
- vi. Services of the investigators for **at least** 5 per cent verification of filled in schedules by DICGC at all the selected centres.

\$\$ Remuneration to be paid to Investigators by the Agency: The agency must pay minimum remuneration to the investigators. A minimum amount of Rs.175/- per schedule/ interview and a minimum daily allowance (including travel expenses) of Rs.290/- per day must be paid to the investigator.

2. Certified that we have read and understood all the terms and conditions in the Tender Document and that our company/firm, <**Name_of_Agency**> do hereby unconditionally accept all the Terms and Conditions set out by the Bank in the Tender Document.

Date:
Place:

Signature of the Authorised Signatory
 (Name of Agency)
 Seal of Agency

Pro-forma of Performance Bank Guarantee

(For successful financial bidder)

(Submitted after going through the formal agreement)

Bank Guarantee No. **(Number)** dated **(Date in words)**

The Chief General Manager
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Reserve Bank of India, 2nd Floor,
Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008

Dear Sir,

WHEREAS **(Name of the successful bidder)** hereinafter called “Successful Bidder” has undertaken, Annual Contract No. **(Ref. No)** dated **(Date)** to conduct **(Survey Name)** hereinafter called “the Contract” in pursuance of Request for Empanelment Document dated **(Date)** and Request for Quotation dated **(Date)** issued by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

AND WHEREAS it is one of the terms of the tender document that the successful bidder has to submit a performance bank guarantee by a scheduled bank for entering into a contract.

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said contract that the successful bidder shall furnish you with a bank guarantee by a schedule bank for the sum specified therein as security for the compliance with the successful bidder performance obligations in accordance with the contract.

AND WHEREAS we **(Bank name)**, a company incorporate under the Companies Act, 1956 and carrying on the business of banking under the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at **(Bank name and full address)** have agreed to give guarantee for the successful bidder.

- 1) THEREFORE, WE here by affirm that we are guarantors and responsible to you up to a total sum of **(Rupees in number and words)** only and we undertake to you, upon your first written demand declaring the successful bidder to be in default under the

contract and without demur cavil or argument, any sum or sums within the amount as aforesaid, without your needing to prove or to show the grounds or reason for your demand or the sum specified therein.

- 2) A letter from your office that the successful bidder has committed default in the due and faithful performance of all or any of its obligations under and in accordance with the contract shall be conclusive, final and binding on us. We further agree that you shall be the sole judge as to whether the successful bidder is in default in due and faithful performance of its obligations under the contract and your decision that he is in default shall be final and binding on us notwithstanding any differences between you and successful bidder or any disputes between you and him pending before an Arbitrator or any other court or tribunal or authority.
- 3) In order to give effect to this guarantee you shall be entitled to act as if we are the principal debtor and any change in our constitution or that of successful bidder shall not, in any way, or manner affect our liability or obligation under this guarantee.
- 4) You shall have liberty, without affecting in any manner our liability under this guarantee, to vary at any time, the terms and conditions of the contract or to extend the time or period for the compliance or to postpone for any time the exercise of any of your rights or enforce or forebear from enforcing any of the terms and conditions of the contract and we shall not be released from our liability or obligation under this guarantee by any exercise of such liberty by you or other forbearance, indulgence, act or omission on your part.
- 5) We undertake not to revoke this guarantee during its currency.
- 6) Any notice by way of request, demand or otherwise hereunder may be sent by the post addressed to us at the above referred branch, which shall be deemed to have been duly authorized to receive such notice and to effect payment thereof forthwith, and if sent by post it shall be deemed to have been given at the time when it ought to have been delivered in due course of post and in proving such notice, when given by post, it shall be sufficient to prove that the envelope containing the notice was posted and a certificate signed by any of your officers that the envelope was so posted shall be conclusive.

- 7) This guarantee shall come into force with immediate effect and shall remain in force and effect for the period up to **(Date)** or until it is released by you pursuant to the provisions of the contract.

Date:

Place:

For and on behalf of

By:

(Signature) (Name) (Designation) (Address)

SIGNED, SEALED AND DELIVERED